सामान्यत: वह सेना जीतती है, जिसके अधिकारियों और सैनिकों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है। -सुन त्जू

त्योहारों के मौसम में, जीएसटी सुधारों की बदौलत बाजार में मौजूद ज्यादातर उत्पादों की कीमतों में कमी निश्चित ही मांग को बढ़ाएगी। अनिश्चित वैश्विक हालात में घरेलू बाजार में उम्मीदें भर देने वाले ये सुधार कुछ चुनौतियों के बावजूद स्वागतयोग्य हैं।

कर से कल्याण

नवरात्रि के पहले ही दिन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में सुधारों के लागू होने के साथ ही देश में कर प्रणाली के एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है, जिसमें कराधान महज राजस्व संग्रह का साधन नहीं, बल्कि सही मायनों में आम आदमी के कल्याण का साधन बनता दिख रहा है। दरअसल, 2017 में जीएसटी की शुरुआत के बाद, यह दूसरा चरण है, जिसमें जीएसटी के मुख्य रूप से पांच और 18 फीसदी के दो ही स्लैब रह गए हैं। इस सुधार को लेकर उत्साह का कारण इससे ही समझा जा सकता है कि अब खाने-पीने की करीब 90 फीसदी चीजों पर शून्य कर है। दाल, चावल, आटा, रोटी तो सस्ती हुई ही हैं, इसके अलावा दूध, किराने के सामान, दवाइयों और कपड़ों पर कर की दर को पांच फीसदी तक कम कर दिया गया है। इससे दैनिक जीवन की लागत कम होगी, जो खासकर निम्न आयवर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। जाहिर है कि एक सामान्य परिवार की इससे जो बचत होगी, वही जरूरत पड़ने पर शिक्षा, स्वास्थ्य या दूसरी जरूरतों पर खर्च हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, कृषि, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई), ट्रैक्टर, उर्वरक और कृषि मशीनरी पर अब 12-18 फीसदी के बजाय सिर्फ पांच फीसदी कर लगेगा, जिससे खेती अधिक उत्पादक और लागत-कुशल बनेगी, साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए लागत कम होगी और ग्रामीण मांग मजबूत होगी। ऑटो क्षेत्र, छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर कर घटने से मध्यमवर्गीय परिवारों को वास्तविक राहत मिलेगी और इससे खासकर टियर-2 और 3 शहरों में मांग में भी इजाफा होगा। स्वास्थ्य व जीवन बीमा पॉलिसियों पर लगने वाले प्रीमियम, जिन पर पहले 18 फीसदी कर लगता था, अब उनके जीएसटी-मुक्त होने से ज्यादा से ज्यादा परिवारों को बीमा कराने का प्रोत्साहन मिलेगा। जीएसटी दरों में बदलाव का इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता था। त्योहारों के मौसम में, जब ज्यादातर लोग अधिक खरीदारी करते हैं, तब बाजार में मौजूद अधिकतर उत्पादों की कीमतों में

कमी निश्चित ही मांग को बढ़ाएगी। अगर उपभोक्ता को इसका लाभ न मिल रहा हो, तो टोलफ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। हालांकि, नई व्यवस्था में प्रारंभिक समायोजन और राजस्व में कमी जैसी चुनौतियां हैं। दूसरी बात यह कि कर दरों की श्रेणियां कम करने से सरलता तो आती है, लेकिन कौन-सी वस्तु किस श्रेणी में रखी जाए, इस तरह के संशय भी पैदा होते हैं। लेकिन जब भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने फैसले बाजार में अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं, तब जीएसटी दरों में आई ताजा कमी यकीनन बाजारों में उम्मीद पैदा करेगी। जीएसटी 2.0 आम आदमी के लिए निस्संदेह एक नई सुबह जैसा है, जिसमें वह भी विकास का हिस्सा बन सकेगा।

क्या हमारी फौज बदल रही है

कोलकाता में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में सेना के भविष्य के सुधारों पर जोर दिया गया। सशस्त्र बल लगातार एकीकरण और एकजुटता की ओर बढ़ रहे हैं। अंततः एकीकृत थिएटर कमांड का निर्माण होगा, जो फिलहाल कुछ दूर है। तब तक ऐसे क्रमिक कदम उठाए जाते रहेंगे।

हर्ष कक्कड़
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। सुधारों का उद्देश्य 'सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत, युद्ध के लिए तैयार और बहु-क्षेत्रीय एकीकृत अभियानों में सक्षम बल में बदलना' होगा। इसमें 'एकजुटता और एकीकरण पहल को बढ़ावा देना और एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना को सुगम बनाना' भी शामिल है। इसके अलावा अन्य सुधार भी होंगे। हालांकि, एकीकृत थिएटर कमांड पर सेनाओं के बीच मतभेद हैं। जहां थलसेना और नौसेना इसके गठन की इच्छा रखती हैं, वहीं वायुसेना अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सैन्य क्षमता घटने की आशंका के चलते इसके विपरीत सोचती है। सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि इन्हें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर तैयार करना होगा। सीडीएस ने बार-बार कहा है कि इसके कार्यान्वयन से पहले तीनों सेनाओं की राय ली जाएगी।

कोलकाता में संपन्न संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भविष्य के सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। सम्मेलन का विषय था 'सुधार का वर्ष-भविष्य के लिए परिवर्तन।' ऐसा आयोजन 2023 में भी हुआ था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर जोर दिया।

रक्षा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित वायु रक्षा की सुदर्शन चक्र परियोजना का जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने जॉइंट मिलिटरी स्पेस डॉक्टरिन (जेएमसी) भी जारी किया। सम्मेलन के दौरान सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और अंतरिक्ष, साइबर तथा विशेष अभियानों के क्षेत्रों में संस्थागत ढांचों में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सीडीएस ने सम्मेलन के अंतिम दिन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख किया और समूह ने उनके कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप पर चर्चा की।

सम्मेलन के दौरान तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता बढ़ाने वाले कुछ बड़े फैसले लिए गए। सीडीएस के अधीन काम करने वाले और इस कार्यक्रम का समन्वय करने वाले आईडीएस (एकीकृत रक्षा स्टाफ) मुख्यालय ने ट्वीट किया कि 'संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के अंतिम दिन, सभी प्रमुखों और कमांडरों द्वारा तीनों सेनाओं की शिक्षा शाखाओं का विलय करके एक त्रि-सेवा शिक्षा कोर बनाने के निर्णय की घोषणा की गई।'

इसके अलावा, तीन संयुक्त सैन्य स्टेशनों के गठन के निर्णय की भी घोषणा की गई, जो देश में पहली बार हो रहा है। तीनों सेनाओं का शिक्षा विभाग गैरिसन, सैनिक स्कूलों और व्यक्तिगत सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों में सैनिकों के शैक्षिक स्तर को समान रूप से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। सेना ने पहले अपनी शिक्षा वाहिनी को साइबर, सूचना प्रौद्योगिकी और भाषाई क्षमताओं सहित व्यापक उद्देश्यों के साथ आर्मी नॉलेज एंड एनेबलर्स कोर में पुनर्गठित करने की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और धारणा प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी को संभालना था। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की नियुक्ति शुरू हो चुकी है। आईडीएस मुख्यालय की प्रारंभिक घोषणा में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह नौसेना और वायु सेना के लिए भी मानक होगा।

साथ ही, अगर शिक्षा शाखा का विलय अपने वर्तमान स्वरूप में होता है, तो सेना के कोर के पुनर्निर्देशन के इरादे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक होने में अभी समय लग सकता है। जहां तक संयुक्त सैन्य स्टेशनों के निर्माण की बात है, तो सरकार के निर्णय के आधार पर, मौजूदा छावनियों को सैन्य स्टेशनों में परिवर्तित किया जा रहा है और नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर निकायों को सौंपा जा रहा है।

कई छावनियां वर्तमान में सैन्य स्टेशनों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में हैं। सैन्य स्टेशन वे स्थान हैं, जहां सैनिकों को उनके परिवारों के साथ रखा जाता है और प्रशिक्षण भी होता है। मौजूदा संयुक्त सैन्य स्टेशन केवल अंडमान और निकोबार कमान के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त परिचालन रसद केंद्र पहले से ही कार्यरत हैं।

इस समय जहां एक स्टेशन पर एक से ज्यादा सैन्य सेवाएं हैं, वहां प्रत्येक सेना अपनी अलग व्यवस्था और सुविधाएं रखती है। क्लब और अस्पताल जैसी कुछ सुविधाएं सभी के लिए समान हैं। नई नीति का अर्थ होगा कि सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं वरिष्ठ सेवा के नियंत्रण में होंगी, जो उन्हें एक ही रोस्टर के तहत आवंटित करेंगी। यह कैसे काम करेगा, यह देखना बाकी है।

थिएटराइजेशन का उद्देश्य सेना की तीनों सेवाओं और उनके संसाधनों को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एकल, एकीकृत कमान संरचना के तहत परिचालन तैनाती के लिए विशिष्ट 'थिएटर' कमानों में एकीकृत करना है। तीन संयुक्त सैन्य स्टेशन बनाने का फैसला भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर एकीकरण लाने में कारगर तो होगा ही, इससे बड़े एकीकृत थिएटर कमान के लिए जनशक्ति, बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के अनुकूलन में भी मदद मिलेगी। इससे संसाधनों के बेहतर उपयोग से आर्थिक बचत तो होगी ही, आधुनिक युद्ध और आपदा राहत जैसे साझा अभियानों को पूरा करने में भी भारतीय सेना की क्षमता बढ़ेगी और सीमाओं की बेहतर ढंग से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

हाल में कोलकाता में हुए सम्मेलन में तीन संयुक्त स्टेशनों के निर्माण की घोषणा की गई है, जहां इन्हें शुरू में परीक्षण के तौर पर लागू किया जाएगा। हालांकि, स्टेशन कहां होंगे, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षण में एक-एक स्टेशन शामिल होगा, जहां एक सेवा प्रमुख हितधारक है। हालांकि, सैन्य ठिकानों को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन अन्य सुविधाओं को मिला दिया जाएगा। सशस्त्र बल लगातार एकीकरण और एकजुटता की ओर बढ़ रहे हैं। अंततः एकीकृत थिएटर कमांड का निर्माण होगा, जो अभी कुछ दूर है। तब तक ऐसे क्रमिक कदम उठाए जाते रहेंगे।

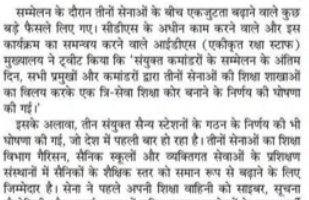

edit@amarujala.com

जीवन धारा

ओरिसन स्वेट मार्डे

हम कल्पना और प्रत्याशा में जीने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान में और अभी आनंद लेने की अपनी बहुत-सी क्षमता खो देते हैं। हम कल के लिए जी रहे हैं, और जब कल आएगा, तो भी कल के लिए ही जिएंगे।

आज जो है, उसी का आनंद उठाएं

यदि किसी अन्य ग्रह के निवासी को धरती की यात्रा करने का अवसर मिले, तो वह शायद यह सोचे कि यहां के लोग किसी ऐसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं, जो आगे है, किसी अन्य गंतव्य की ओर, और जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं, वह केवल एक पारगमन स्थल है, जहां वे केवल इतना सामान खोलते हैं, जितना उन्हें अस्थायी ठहराव के लिए चाहिए। यह आगंतुक बहुत कम लोगों को वास्तव में वर्तमान में, यहीं और अभी जीते हुए पाएगा। वह पाएगा कि अधिकांश लोगों की नजरें किसी दूर की चीज पर टिकी हुई हैं, किसी आने वाली चीज पर। वे वास्तव में आज स्थिर नहीं हैं, वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, लेकिन वे निश्चित हैं कि वे कल या अगले साल जीएंगे, जब व्यवसाय बेहतर हो जाएगा, उनकी किस्मत बढ़ जाएगी, जब वे अपने नए घर में चले जाएंगे, नए फर्नीचर प्राप्त करेंगे, नई कार लेंगे, उन चीजों से छुटकारा पा लेंगे, जो अभी परेशान करती हैं, और उनके चारों ओर सब कुछ ऐसा होगा जो उन्हें आराम देगा। तब वे खुश होंगे। लेकिन वे वास्तव में आज खुद का आनंद नहीं ले रहे हैं।

हमारी आंखें इतनी भविष्य पर केंद्रित हैं, किसी दूर के लक्ष्य पर, कि हम अपने चारों ओर की सुंदरता और वैभव को नहीं देख पाते। हमारी आंखें निकट की चीजों के लिए केंद्रित नहीं हैं, बल्कि दूर की चीजों के लिए हैं। हम कल्पना और प्रत्याशा में जीने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम वर्तमान में और अभी आनंद लेने की अपनी बहुत-सी क्षमता खो देते हैं। हम कल के लिए जी रहे हैं, और जब कल आएगा, तो वह अभी भी कल ही होगा! हम इंद्रधनुष का पीछा करने वाले बच्चों की तरह हैं। काश हम उस तक पहुंच पाते, तो कितना आनंद होता? हम अपना जीवन 'भविष्य' में व्यापार करने में बिताते हैं। हम कभी यह विश्वास नहीं करते कि हम अब तक अपने सर्वोत्तम जीवन के वर्षों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें हमेशा यकीन होता है कि जीवन का वह आदर्श समय आ रहा है। हममें से अधिकांश असंतुष्ट, बेचैन, घबराए हुए और दुखी हैं। हमारी आंखों में एक दूर की नजर है, जो दिखाती है कि हम आज से संतुष्ट नहीं हैं, हम वास्तव में यहां और अभी जी नहीं रहे हैं, मन वर्तमान से परे किसी चीज पर है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उचित यही है कि कहीं भी रहें, सिवाय यहीं और अभी के। बहुत-से लोग अतीत में खोये हुए समृद्ध अवसरों, शानदार मौकों के बारे में सोचते रहते हैं, जिन्हें उन्होंने गंवा दिया है और ऐसा करते हुए, वे उस अनमोल वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं जो आज उन्हें बहुत कम महत्व का लगता है। इस दुनिया में हमें जीवन का शहद प्राप्त करना ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खी हर तरह के फूलों और खरपतवारों से मिठास चूसती है। पूरी दुनिया बिना काम की खुशियों की खानों से भरी है। हम जहां भी जाते हैं, हमें हर तरह की खुशी देने वाली सामग्री मिल जाती है, बस हमें उसे निकालना होता है। हर चीज सार्थक है, अगर हम उसे और उसके महत्व को समझ लें। जिंदगी का आधा आनंद तो छोटी-छोटी चीजों में ही है।

छोटी चीजों में तलाशें खुशियां

सूत्र

हमें लगता है कि वह 'एक दिन' जरूर आएगा। लेकिन इस इंतजार में हम सब कुछ गंवा देते हैं। हममें से ज्यादातर असंतुष्ट, बेचैन, घबराए हुए और दुखी हैं। दूर की सोचना अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान को बर्बाद करके नहीं, बल्कि इसे जी कर। इस भागदौड़ में अंतिम समय आ जाएगा और एहसास भी नहीं होगा, इसलिए छोटी-छोटी चीजों में खुशियां तलाशें।

दूसरा पहलू

वैज्ञानिकों की सबसे पहली खोज बेबीलोन का खगोल विज्ञान था। बेबीलोनवासी आज के इराक क्षेत्र में रहते थे।

वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या खोजा

विज्ञान आम तौर पर व्यवस्थित और औपचारिक ज्ञान पर निर्भर है। लेकिन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले क्या खोजा होगा? विज्ञान इतिहासकार होने के नाते मैं बता सकता हूं कि वैज्ञानिकों की सबसे पहली खोज बेबीलोन का खगोल विज्ञान है। बेबीलोनवासी 2,500 से 4,000 वर्ष पूर्व आज के इराक क्षेत्र में रहते थे। उनका खगोल विज्ञान इसलिए खास था, क्योंकि बेबीलोन के उस समय लेखकों (ज्ञान के संरक्षकों) ने संगठित तरीके से सूर्य, चंद्रमा, तारों और ग्रहों के आकाश में घूमने के तरीकों का अवलोकन कर उन्हें दर्ज किया और अंततः गणितीय रूप से भविष्यवाणी की।

जेम्स बर्क

घड़ी के आविष्कार से पहले लोग आकाश देखकर समय जानते थे। पर, बेबीलोनवासियों के लिए खगोलशास्त्र सिर्फ समय देखने का जरिया नहीं था।

घड़ी के आविष्कार से पहले लोग आकाश देखकर समय जानते थे। पर, बेबीलोनवासियों के लिए खगोलशास्त्र सिर्फ समय देखने का जरिया नहीं था। आज की तरह, मौसम ऋतुओं के साथ बदलता था, फसलें बोई और काटी जाती थीं; त्योहार मनाए जाते थे; लोग पैदा होते, बूढ़े होते और मरते थे, सब पूर्वानुमानित होता था। बेबीलोन के लोग भौगोलिक घटनाओं और अकाल, बीमारी आदि को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। वे ग्रहों की गति में बदलाव या ग्रहण जैसी दुर्लभ घटनाओं को पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में देखते थे। खगोलशास्त्रियों के पास एक पुस्तक थी, जिसमें शकुनों और उनके अर्थों का विवरण था। बेबीलोन में खगोल विज्ञान की नींव मुल. अपिन नामक एक पुस्तक में रखी गई थी। इसमें तारों की स्थिति, वर्ष में वे पहली बार कब दिखाई देंगे, सूर्य और चंद्रमा के पथ, ग्रहों के रात्रि आकाश में दिखाई देने की अवधि, और अन्य मूलभूत खगोलीय ज्ञान दर्ज थे। बाद में, उन्होंने खगोलीय डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति के साथ मौसम और अनाज की कीमतें भी लिखी जाती थीं। ये डायरियां 700 से ज्यादा वर्षों तक रखी गईं, जिससे वे शायद अब तक की सबसे लंबी चलने वाली वैज्ञानिक परियोजना बन गईं। डायरियों के अभिलेखों ने बेबीलोन के लेखकों को खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद की। उन्होंने एफेमेराइड्स नाम की तालिकाएं बनाईं, जो भविष्य की खगोलीय घटनाओं को दिखाती थीं। एफेमेराइड्स आज की खगोलीय तालिकाओं की पूर्वज हैं, जैसे नासा की ग्रहण तालिका, जो साल 3,000 तक की भविष्यवाणी करती है। बेबीलोन के लोग 60 की इकाइयों का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि हम आज भी करते हैं। आज भी हम एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड बताते हैं, और जब भी हम समय बता रहे होते हैं, तो हम सबसे प्राचीन विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। -द कन्वर्सेशन से

मुल. अपिन नामक पुस्तक में तारों की स्थिति, वर्ष में वे पहली बार कब दिखाई देंगे, सूर्य और चंद्रमा के पथ, ग्रहों के रात्रि आकाश में दिखाई देने की अवधि, और अन्य मूलभूत खगोलीय ज्ञान दर्ज थे।

आंकड़े

कृषि निर्यात

भारत दुनिया के कई देशों में अपने कृषि उत्पादों को निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा कृषि निर्यात यूएई को किया गया।

यूएई	7.17%
सऊदी अरब	7.12%
अमेरिका	6.84%
इराक	5.15%
वियतनाम	4.51%

आंकड़े भारत के कृषि निर्यात के प्रतिशत में | स्रोत : DGCIS

माता सीता के हरण से प्रभु श्रीराम चिंतित थे। देवर्षि नारद ने कहा, 'प्रभु आप शारदीय नवरात्र में मां भगवती का अनुष्ठान करें, जिससे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होगी।'

श्रीराम ने किया मां का अनुष्ठान

शारदीय नवरात्र के दौरान विशेष अनुष्ठान और व्रत को लेकर कई कथाएं हैं। पुराणों के अनुसार, भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले मां दुर्गा का नौ दिन तक उपवास रखा था। बताते हैं कि भगवान श्रीराम माता सीता के हरण से चिंतित थे। यह देखकर देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए उस जगह पहुंचे जहां प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण जी थे। प्रभु श्रीराम को चिंतित देखकर नारद जी ने कहा, 'इस आश्विन महीने में आने वाले नवरात्र का आप व्रत रखें और मां भगवती का अनुष्ठान करें। उनके नाम का जप करने से हर तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः इस कठिन परिस्थिति में आपको यह व्रत जरूर करना चाहिए।'

इसके बाद प्रभु श्रीराम ने नारद जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। नारद मुनि के दिशा-निर्देश पर प्रभु श्रीराम ने किष्किन्धा पर्वत पर भगवती मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ इस अनुष्ठान का पालन किया।

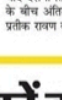

अंतर्यात्रा
संकलित

उपवास रखने से माता भगवती प्रसन्न हुईं और महाष्टमी तिथि की रात्रि में उन्होंने प्रकट होकर दोनों भाइयों को दर्शन दिए। साथ ही माता ने श्रीराम को विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद दशमी तिथि को जब प्रभु श्रीराम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ, तब उन्होंने अधर्म के प्रतीक रावण का वध कर विजय प्राप्त की।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 23 सितंबर, 1951

हिंदू कोड-सभी हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों पर लागू होगा

हिंदू कोड सभी हिंदुओं—बौद्धों, जैनों व सिखों पर भी लागू होगा

हिंदू कोड बिल की दूसरी धारा संसद में पारित हो गई, जिसके अनुसार, यह कोड हिंदू धर्म मानने वालों के साथ ही जैन, बौद्ध और सिख धर्म पर भी लागू होगा। मुसलमानों, मसीहियों, पारसियों और यहूदियों पर यह कोड लागू नहीं होगा।

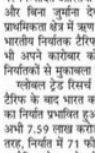

टैरिफ से बढ़ सकता है बैंकों का एनपीए

बैंक निर्यातकों को शुरू से ही मदद मुहैया कराते रहे हैं, लेकिन अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद ऋण देने में संकोच कर रहे हैं।

सतीश सिंह
आर्थिकी

पचास प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद भारतीय निर्यातकों के विविध संगठनों ने भारतीय रिजर्व बैंक से अमेरिका निर्यात करने वाले निर्यातकों को ऋण चुकाने में राहत, ऋण स्थगन, गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के नियमों में ढील देने और बिना जुर्माना देय तिथि को आगे बढ़ाने और प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि भारतीय निर्यातक टैरिफ से होने वाले नुकसान के बाद भी अपने कारोबार को जिंदा रख सकें और विदेशी निर्यातकों से मुकाबला करने में समर्थ बन सकें।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ के बाद भारत का करीब 5.4 लाख करोड़ रुपये का निर्यात प्रभावित हुआ है, जबकि भारत अमेरिका को अभी 7.59 लाख करोड़ रुपये का निर्यात करता है। इस तरह, निर्यात में 71 फीसदी गिरावट का अनुमान है।

टैरिफ से कपड़े, जेम्स-ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय उत्पाद महंगे हो गए हैं और इनकी मांग में लगभग 70 प्रतिशत की कमी आ सकती है। वहीं, चीन,

वियतनाम जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ती कीमत पर अमेरिका में बेच रहे हैं, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी कम हुई है। एक अनुमान के मुताबिक, टैरिफ से भारतीय निर्यातकों की लागत दूसरे देशों के निर्यातकों की तुलना में 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जिसकी भरपाई करना भारतीय निर्यातकों के लिए आसान नहीं होगा।

टैरिफ से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यातकों को सबसे अधिक नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि इस क्षेत्र की वित्तीय क्षमता कम है। यह क्षेत्र मुख्य तौर पर कपड़े, रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इलेक्ट्रिकल उत्पाद, लेदर के उत्पाद, फुटवियर, केमिकल उत्पाद, खाद्य व पेय पदार्थ, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स, फार्मा, मेडिकल उपकरणों आदि का निर्यात करता है और इस क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। भारत अमेरिका से शीर्ष पांच उत्पाद जैसे, क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कोयला व कोक खरीदता है, जबकि पेट्रोलियम, दवा व फार्मा, मोती व महंगे पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी व इक्विपमेंट्स आदि निर्यात करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने अमेरिका को 6.75 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया था, जबकि आयात किया केवल 3.67 लाख करोड़ रुपये का। इस तरह, 10.42 लाख करोड़ रुपये के कुल कारोबार में भारत के लिए 3.07 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस ट्रेड बैलेंस रहा।

देश के बैंक निर्यातकों को मदद कर रहे हैं। प्री-शिपमेंट क्रेडिट के तहत बैंक, उत्पादों के निर्माण, कच्चे माल की खरीद, कामगारों को वेतन आदि के लिए ऋण मुहैया कराते हैं, जबकि पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट के अंतर्गत ये निर्यातकों को उनके माल का तुरंत भुगतान करके आयातकों से पैसों की वसूली का जोखिम खुद उठाते हैं। बैंक निर्यातकों के प्रतिनिधि के तौर पर लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के जरिये आयातक को भुगतान की गारंटी देते हैं और गारंटी के जरिये सौदा पूरा नहीं होने पर निर्यातकों को होने वाले संभावित नुकसान के जोखिम को कम करते हैं। एक्जिम बैंक निर्यातकों को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सहायता उपलब्ध करता है, बैंकों के अलावा, उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो (बीआईएस), सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी), वाणिज्य विभाग, विदेश विभाग, और ट्रेजरी विभाग आदि सरकारी एजेंसियां भी निर्यातकों को मदद मुहैया कराती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 29 दिसंबर, 2023 तक बैंकों द्वारा निर्यात के मद में दिए गए ऋण की आउटस्टैंडिंग 12,940 करोड़ रुपये थी, जो 26 जनवरी 2024 तक बढ़कर 20,489 करोड़ रुपये हो गई थी, लेकिन 27 जून 2025 तक यह राशि घटकर 13047 करोड़ रुपये रह गई। निर्यातकों को कम ऋण वितरित करने का मुख्य कारण अमेरिकी टैरिफ है, क्योंकि इसके कारण बैंक निर्यातकों को ऋण देने में सावधानी बरत रहे हैं। दरअसल, उन्हें लोन के एनपीए में तब्दील होने का डर सता रहा है। इसके अलावा, इस कारण अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात वॉल्यूम में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में निर्यात ऋण अभी कुल मांग का मात्र 28.5 फीसदी है, जिसे अपेक्षित नहीं कहा जा सकता है, जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2024 में निर्यात का 21.18 प्रतिशत का योगदान रहा था। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों और मुद्रा के मौजूदा विनिमय दर से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिकी टैरिफ से अमेरिका निर्यात करने वाले निर्यातकों खास करके एमएसएमई निर्यातकों को सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की तरफ से राहत देने की जरूरत है, अन्यथा बैंकों पर एनपीए का दबाव बढ़ेगा साथ ही साथ यह निर्यात और भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए भी मुफीद नहीं होगा।

राष्ट्रीय सहारा

पटना • मंगलवार • 23 सितम्बर• 2025

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

ज्ञानी जन विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी पुरुष आवश्यकता से और पशु स्वभाव से
-कौटिल्य

कटौती का मलहम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नाम दिए गए संबोधन में जीएसटी यानी वस्तु व सेवा कर की नई दरों का ऐलान किया और इसे त्योहारी मौसम का बचत उत्सव बताया। गरीब, मध्यवर्गीय, नियो मिडिल क्लास, युवा, किसानों, महिलाओं, दुकानदारों व उद्यमी सबको इस बचत उत्सव से फायदा होने की भी बात की। तकरीबन उन्नीस मिनट के इस संबोधन में मोदी ने माना कि देश में दर्जनों टैक्स थे। उन्हें टैक्स जंजाल बताते हुए कहा कि नई जीएसटी दरों से व्यापार आसान होगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और आयकर में छूट मिलेगी, जिससे ढाई लाख करोड़ रुपये की बचत के अवसर मिलेंगे। विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम और देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देने पर भी मोदी ने बल दिया। असल सवाल है कि इन

बदलावों के पीछे देश की आर्थिक जरूरत है या यह सिर्फ राजनीतिक मुनाफे के मद्देनजर किए गए हैं। खाने-पीने की चीजों में मामूली कमी से बेतहाशा बढ़ी महंगाई तो कम नहीं होने वाली। बीमा प्रीमियम व गाड़ियों की कीमत पर पड़ने वाले असर का लाभ लेने वालों की संख्या सीमित होती है। हालांकि बीमा कंपनियों को इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। अर्थ-विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी में बहुत अनियमितताएं थीं, जिन्हें सरकार को बहुत पहले सुधारना था। मगर बिहार चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार द्वारा उठाया गया यह राजनीतिक दांव हो सकता है। मोदी पर विश्वास जताने वाले बड़े मध्यवर्ग से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर तबका बढ़ती महंगाई से बुरी तरह त्रस्त है। त्योहारी मौसम में जनता की क्रय क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। स्वदेशी उत्पादों को महत्त्व देने की बात मोदी पहले भी करते रहे हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा धमकीस्वरूप सर्वाधिक टैरिफ लादने के बाद से देश में निर्मित चीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत स्वयं सरकार महसूस रही है। इसके लिए विभिन्न अवरोधों व लालफीताशाही को रोकना होगा। सरकार को 2024 तक राजस्व का 70 हिस्सा जीएसटी के 18 वाले स्लैब से प्रप्त हुआ था। उम्मीद से कहीं अधिक यानी बीते वित्त वर्ष में बीस लाख करोड़ रुपये की वसूली कर सरकार के वारे-न्यारे हो गए। मुफ्त की योजनाओं के बूते सीमित संख्या में जनता को प्रलोभन देने की बजाए हर नागरिक तक कटौती का लाभ देने की इस पहल के नतीजे बेहतर होने की उम्मीदों पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।

आत्मनिर्भरता का संबल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का मुख्य दुश्मन अन्य देशों पर उसकी निर्भरता है। गुजरात में भावनगर के गांधी मैदान में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर जहाजों तक हर चीज का स्वदेशी उत्पादन करने का आह्वान किया। 34,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है- आत्मनिर्भरता। 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य बाहरी ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। न ही राष्ट्रीय विकास का संकल्प विदेशी निर्भरता पर आधारित हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दूसरों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यदि 140 करोड़ की आबादी वाला देश दूसरों पर निर्भर है, तो यह राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ समझौता है। गर्ज यह कि भारत को उस लोकप्रिय कहावत

के अनुसार चलना है जिसमें आगाह किया गया है कि दूसरों पर निर्भर व्यक्ति सुख की कामना नहीं कर सकता। आत्मनिर्भरता व्यक्ति या किसी भी राष्ट्र का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए बुनियादी शर्त है। लेकिन यह भी सच है कि विश्व आज ग्लोबल गांव की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसलिए हमें आत्मनिर्भरता की पारंपरिक अवधारणा को तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और भू-राजनीतिक जटिलताओं के मुताबिक ढालना होगा। ऐसा किए बिना कोई भी देश दावा नहीं कर सकता कि वह अपने लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर ही रहा है। क्षेत्र विशेष में लाभ की स्थिति को माकूल बना लेना अभीष्ट होगा। श्रेयस्कर तो यही है कि देश उन क्षेत्रों में ताकतवर बनने के लिए पूरी ताकत झोंक दे जिनमें बनिस्बत लाभ की स्थिति में है। दरअसल, तमाम देश वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शृंखला में गुंथे हुए हैं। अपने स्तर पर उन माकूल और वहनीय वस्तुओं और सेवाओं, जिनके उत्पादन में हम सहूलियत के लिहाज से बेहतर स्थिति में हैं, की आपूर्ति में अच्छा प्रदर्शन कर लें तो यकीनन किसी भी देश की बेतुकी शर्तों के सामने झुकने की नौबत नहीं आएगी। दरअसल, वैश्विक आपूर्ति शृंखला में प्रासंगिकता और अपरिहार्यता बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। कहना न होगा कि इस संदर्भ में विकसित भारत का संकल्प हमारी सबसे बड़ी ताकत और आश्वस्ति है।

चर्चा/मुनीष भाटिया

विदेश मोह में जकड़ा युवा

आज के समय में, भारतीय युवाओं की आकांक्षाएं तेजी से बदल रही हैं। उनमें से प्रमुख है विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना, बेहतर नौकरी पाना या वहीं बस जाना। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से ग्रामीण भारत में अधिक देखने को मिल रही है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और बिहार जैसे राज्यों में। यहां के गांवों में अक्सर खालीपन का एहसास होने लगा है और खेतों में सूनापन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी रोजगार और अवसरों की तलाश में शहरों की ओर, और उससे भी आगे, विदेशों की ओर रुख कर रही है। माता-पिता भी अपने बच्चों के विदेश जाने के सपने को पूरा करने के लिए पुश्तैनी जमीन और जायदाद तक बेच देते हैं, जिससे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है।

भारतीय युवाओं के बीच विदेश जाने की इस प्रबल इच्छा के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि वे मानते हैं कि एक समृद्ध और सम्मानजनक जीवन केवल विदेशों में ही संभव है। उन्हें लगता है कि विदेशों में कमाई अधिक होगी और जीवनशैली अधिक सुविधाजनक होगी। यह सोच अक्सर मीडिया, सोशल मीडिया और विदेशों में रहने वाले रिश्तेदारों की कहानियों से प्रभावित होती है, जो सिर्फ चमक-दमक वाली तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि, सच्चाई इससे बहुत अलग है। विदेश जाकर हर किसी को उच्च पद या शानदार नौकरी नहीं मिलती। 2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1.8 करोड़ भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, और इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उच्च कौशल या शिक्षा के बावजूद निम्न-स्तरीय काम करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या विदेश जाना ही एकमात्र विकल्प है? यदि कोई युवा विदेश में छोटे-मोटे काम कर सकता है, तो वही काम वह अपने ही देश में क्यों नहीं कर सकता? फर्क केवल सोच और दृष्टिकोण का है। युवाओं को यह समझना होगा कि अपनी मिट्टी से जुड़कर आगे बढ़ने में जो संतोष है, वह पराए देश में छोटे काम करके भी हासिल नहीं हो सकता। विदेश जाकर अकेले सपने पूरे करने से बेहतर है कि अपने गांव और समाज को साथ लेकर समृद्धि की ओर बढ़ें।

संबोधन के महत्त्व को समझिए

सामयिक

अवधेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन लगभग 19 मिनट का था। विरोधियों की आम प्रतिक्रिया यही है कि केवल जीएसटी या वस्तु और सेवा कर सुधार की ही बात रखनी थी तो उसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई विश्लेपकों और पत्रकारों ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसी तरह का पोस्ट लिखा है। मोदी की छवि अच्छे प्रभावी होने के साथ लोगों की समझ में आ जाए इस तरह से बात रखने वाले वक्ता की है। जैसे ही यह सूचना आई कि प्रधानमंत्री शाम 5:00 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे अनेक तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं।

प्रधानमंत्री के बारे में उनकी पार्टी के शीर्ष लोग भी बोलते हैं कि उनका पूर्व अनुमान लगाना लगभग असंभव होता है। इस कारण शायद देश के बड़े समूह की उम्मीदें ज्यादा रही होंगी। इस समय जिस तरह की चुनौतियां भारत के सामने उत्पन्न हुई हैं, सोशल मीडिया में इतनी बातें आती है कि लोग सभी में शीर्ष नेतृत्व से प्रतिक्रिया की मांग करने लगते हैं। उसमें यदि कुछ लोगों को लगता है कि इतने के लिए संबोधन की आवश्यकता नहीं थी तो यह उनकी सोच हो सकती है। सच कहा जाए तो किसी संबोधन का छोटा होना उसके आवश्यक, प्रासंगिक और महत्त्वपूर्ण न होने का पर्याय नहीं हो सकता। 2017 में जीएसटी की शुरुआत के समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और उसे आर्थिक आजादी की शुरुआत बताया था।

अप्रत्यक्ष करों में इतनी बड़ी कटौती केवल दो दरों पांच प्रतिशत और 18 तक सीमित कर देने जैसे ऐतिहासिक कदम पर वे देश को संबोधित नहीं करें ऐसा संभव नहीं था। उसमें भी इस वर्ष के बजट में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया। ध्यान रखिए, 15 अगस्त को लाल किले के संबोधन से ही उन्होंने सेकंड जेनरेशन रिफॉर्म यानी दूसरी पीढ़ी के सुधार की बात की थी और इसे सतत प्रक्रिया बताया था। इस नाते जीएसटी दरों में परिवर्तन का क्रांतिकारी महत्त्व है। शारदीय नवरात्र और ग्रेगोरियन कैलेंडर से 22 सितम्बर से इसकी शुरुआत करने का महत्त्व भी समझा जाना चाहिए। आखिर नौ दिनों का यह त्योहार शरीर और चित्त की शुद्धि ही नहीं अपनी साधना से बहु स्वरूपा मां दुर्गा को प्रसन्न कर सिद्धि प्राप्त करने की भी है। आप दुर्गा सप्तशती के या देवी सर्वभूतेषु श्लोक को याद करेंगे तो इहलोक और परलोक से मनुष्य की जुड़ी हुई आशाओं में से कोई भी पहलू छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं दासत्वकाल के अवशेषों और मानसिकता से मुक्ति का बार-बार आह्वान किया है तथा भारतीय सभ्यता संस्कृति और

आध्यात्मिक बात की है तो यह उस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त में देवी देवताओं की आराधना के साथ कार्य शुरू करने की हमारी परंपरा है। नवरात्र के आरंभ जैसी अवसरों से अपने व्यापक आर्थिक सुधार के इतने महत्त्वपूर्ण कदम की शुरुआत करते हैं तो राष्ट्र के नाम संबोधन से इसका महत्त्व स्पष्ट होता है।

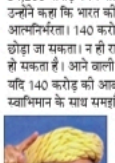

प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भव, बचत उत्सव से लेकर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बातचीत की। सुनने में बड़ा सरल लगता है किंतु भारत के वर्तमान व भविष्य की दृष्टि से इसका व्यापक महत्त्व है। वर्तमान विश्व परिदृश्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संचालन के लिए कोई नियम या तंत्र नहीं है। सभी देशों को अपनी आंतरिक व बाह्य शक्ति के आधार पर ही अस्तित्व बनाए रखने और कार्य करने का यथार्थ सामने है। भारत के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25 सीमा शुल्क फिर रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25 शुल्क लागू कर दिया। अमेरिका विपक्षीय व्यापार में हमारा सबसे ज्यादा 42 से 43 अरब डॉलर का लाभ देने वाला देश है। यहां हमारे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात प्रभावित हुए तो इसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ना है। आप इसका आकलन अपने अनुसार कर सकते हैं। शायद सामान्य समय में भारत रूस से तेल आयात में थोड़ी बहुत कमी कर सऊदी और अन्य जगहों से बढ़ा सकता था। किंतु अभी ऐसा करने का अर्थ देश का दबाव में झुक जाना होगा और इसका आर्थिक प्रभाव भी होगा। विश्व को दिशा देने का लक्ष्य रखने वाला देश कदापि ऐसा नहीं कर सकता। तो यह एक अवसर है हमें भविष्य की दृष्टि से सचेत होकर कदम उठाने का ताकि आने वाले समय में इससे बड़े आघात भी राष्ट्र के रूप में भारत को प्रभावित नहीं कर सकें। रक्षा, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समीकरणों की दृष्टि से भी संपूर्ण विश्व उथल-पुथल के दौर में है। हर देश अपने को और सशक्त करने की दृष्टि से कदम उठा रहा है।

थोड़ी गहराई से देखे तो यह विचारधाराविहीनता का भी युग है जहां संपन्न व प्रभावी व्यक्तित्व, संस्थाएं, संगठन, समूह, समुदाय किसी देश में उथल-पुथल का खतरा पैदा कर सकते हैं। इन सबसे निपटने का कोई एक रास्ता हो सकता है तो यही कि भारत हर दृष्टि से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं और आत्मनिर्भरता का रास्ता राष्ट्र के प्रति स्व भाव के अभियान और स्वदेशी से जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं लंबे समय से 'लोकल फॉर वोकल' की बात तो करते ही रहे हैं आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की दृष्टि से भी सरकार नीतियां बदलती रही है।

इन सारे परिप्रेक्ष्यों को आधार बनाएं तो निष्कर्ष आएगा कि प्रधानमंत्री ने छोटे संबोधन में ही राष्ट्र के लिए एक क्रांति का आह्वान किया है। उन्होंने उद्यमियों, एक-एक व्यक्ति, सभी राज्यों से अपील की है कि मिलजुल कर इस तरह से कम करें, ऐसे नियम बनाएं ताकि स्वदेशी सोच व संसाधनों की बदौलत आत्मनिर्भर बन सकें। यही एकमात्र रास्ता है जिसके बाद कोई देश हमको आर्थिक, सैन्य, तकनीक, वैज्ञानिक किसी दृष्टि से दबाव में लाने का दुस्साहस नहीं करेगा। भारत की दृष्टि से देखें तो नवरात्र के समय से त्योहार का दौर शुरू होता है जिसमें आम परिवार खरीदारी करते हैं। जीएसटी के बदलाव का समय ऐसा चुना गया है कि बाजारों में बिक्री बढ़नी ही है। वैश्विक परिस्थितियों के और बिगड़ने के बावजूद इसका नकारात्मक असर नहीं हो सकता है। इन दृष्टि से प्रधानमंत्री के संबोधन के तात्कालिक एवं दूरगामी महत्त्व को समझा जा सकता है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> प्रधानमंत्री ने छोटे संबोधन में ही राष्ट्र के लिए एक क्रांति का आह्वान किया है। उन्होंने उद्यमियों, एक-एक व्यक्ति, सभी राज्यों से अपील की है कि मिलजुल कर इस तरह से काम करें, ऐसे नियम बनाएं ताकि स्वदेशी सोच व संसाधनों की बदौलत आत्मनिर्भर बन सकें। यही एकमात्र रास्ता है जिसके बाद कोई देश हमको आर्थिक, सैन्य, तकनीक, वैज्ञानिक किसी दृष्टि से दबाव में लाने का दुस्साहस नहीं करेगा

छाछ : पाचन दुरुस्त करने का एक अच्छा विकल्प

- छाछ पाचन के लिए अच्छा विकल्प है। छाछ दही को पानी मिला कर और मथ कर बनाई जाती है, इसलिए इसमें दही की तुलना में फैट और कैलोरी कम होती है। हल्की होने के कारण यह आसानी से पच जाती है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो पाचन दुरुस्त और पेट की जलन कम करता है
- छाछ में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है। एक स्टडी के अनुसार, छाछ मानसून में शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसके सेवन से थकान कम होती है। जब खाना ज्यादा लगे या पाचन में कठिनाई हो तो छाछ पीना सबसे अच्छा रहता है

(मीडिया इनपुट्स)

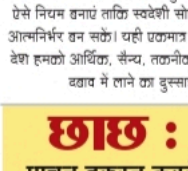

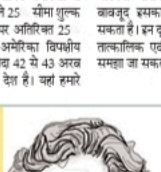

अधिकाधिक खरीदारी की बजाय अगर पर्व को बचत उत्सव की तरह मनाने का आग्रह हो, तिस पर स्वदेशी माल ही लेने का आग्रह किया जाए तो महंगाई के जमाने में समझदार लोग खरीदारी से यथासंभव बचेंगे।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

सहित्य का आकाशदीप

दिनकर जयंती | प्रो. आर.के. जैन

भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षितिज पर कुछ ऐसे सितारे हैं, जिनका जिक्र किए बिना हर चर्चा फीकी रह जाती है। रामधारी सिंह 'दिनकर' उनमें से एक चमकता नाम हैं। वे केवल कवि नहीं थे, बल्कि एक युग की हुंकार, स्वतंत्रता की ललकार और सामाजिक क्रांति का प्रचंड स्वर थे। उनकी लेखनी में वह ज्वाला थी, जो अन्याय के खिलाफ तीक्ष्ण तलवार की तरह चमकती थी और जनमानस के हृदय में आत्मविश्वास की मशाल प्रज्ज्वलित करती थी।

दिनकर की कविताएं केवल साहित्यिक सौंदर्य की कृति नहीं थीं; वे समाज को दिशा देने, उसे झकझोरने और उसमें क्रांतिकारी चेतना जागृत करने का सशक्त हथियार थी। उनके शब्दों में वह ताकत थी, जो कागज को तलवार और स्याही को अमृत में बदल देती थी। उनकी जयंती पर हमें न केवल उनकी साहित्यिक विरासत को सलाम करना चाहिए, बल्कि उनके उन अनछुए पहलुओं को भी उजागर करना चाहिए, जो उनकी प्रासंगिकता को नई पीढ़ी तक ले जाएं। 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे दिनकर का जीवन प्रेरणा की एक जीवंत गाथा है। कम लोग जानते हैं कि उनकी प्रारंभिक कविताएं गांव के सामाजिक-आर्थिक परिवेश से प्रेरित थीं। उनमें बिहार की मिट्टी की सोंधी सुगंध और ग्रामीण भारत की कठोर सच्चाइयां जीवंत रूप में झलकती थीं। उनकी संवेदनशीलता ऐसी थी कि वे आम जन की पीड़ा को न केवल महसूस करते थे, बल्कि उसे अपनी लेखनी में अमर कर देते थे। स्वतंत्रता संग्राम में दिनकर की कविताएं युवाओं के लिए प्रेरणा की अग्नि बनी। 'हिमालय', 'हुंकार' और 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' जैसी रचनाएं केवल कविताएं नहीं, बल्कि स्वाधीनता की जंग में हथियार थी। उनकी कविता 'सामधेनी' ने नौजवानों के दिलों में ऐसी चिंगारी सुलगाई कि कई लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। एक अनकहा तथ्य यह है कि उनकी कुछ रचनाएं इतनी क्रांतिकारी थीं कि ब्रिटिश शासन ने उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। मगर दिनकर की लेखनी कहां रुकने वाली थी! उनकी कविताएं गुप्त रूप से छपती और बंटती रहीं, जन-जन तक उनकी बुलंद आवाज पहुंचाती रहीं। यही वह विशेषता थी, जो उन्हें समकालीन कवियों से अलग करती थी-वे साहित्यिक मंचों की सैर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जनमानस की धड़कनों को थामने और उसे जागृत करने में

सक्षम थे। रामधारी सिंह दिनकर' की कालजयी कृति 'रश्मिरथी' केवल महाभारत के कर्ण की गाथा नहीं, बल्कि सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ एक तीक्ष्ण विद्रोह है। इसे महज पौराणिक कथा का पुनर्लेखन मानना दिनकर की गहन दृष्टि को कमतर करना होगा। 'रश्मिरथी' में कर्ण की पीड़ा और संघर्ष के जरिए दिनकर ने समाज की जड़ता पर करारा प्रहार किया। यह रचना उस दौर में क्रांतिकारी थी, जब साहित्य में सामाजिक सुधारों की गूंज दुर्लभ थी। कर्ण के चरित्र के माध्यम से उन्होंने यह सशक्त संदेश दिया कि प्रतिभा और पराक्रम जन्म या सामाजिक स्थिति की बेड़ियों से परे हैं। 'कुरुक्षेत्र' उनकी एक और कृति है, जो विश्व साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ती है। इसमें दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को महाभारत के युद्ध से जोड़कर युद्ध की भयावहता और शांति की अनिवार्यता को रेखांकित किया। इसकी अनूठी विशेषता यह है कि दिनकर ने युद्ध के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को जिस गहराई से उभारा, वह उस समय के हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व था। दिनकर का योगदान केवल कविता तक सीमित नहीं था। उनके गद्य लेखन और निबंध, विशेष रूप से 'संस्कृति के चार अध्याय', भारतीय संस्कृति की बहुरंगी छटा को एक जीवंत चित्रपट की तरह प्रस्तुत करते हैं। दिनकर की भाषा-शैली उनकी रचनाओं का प्राण थी। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी का उपयोग किया, पर उसमें ऐसी सरलता और जीवंतता भरी कि आम पाठक भी उनके भावों से गहराई से जुड़ सके। उनकी कविताओं में छंदों की मर्यादा थी, तो गद्य में उतनी ही ताकत। उनकी लेखनी में क्रांति का उद्घोष था, तो करुणा और प्रेम की गहनता भी।

उनकी रचना 'उर्वशी' इसका सशक्त प्रमाण है, जो प्रेम और सौंदर्य को न केवल भावनात्मक, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रस्तुत करती है। उनकी जयंती पर हमें यह आत्मसात करना होगा कि दिनकर केवल कवि नहीं, बल्कि युग-द्रष्टा थे, जिनकी लेखनी समय की सीमाओं को लांघकर प्रासंगिक बनी हुई है। अन्याय, विषमता और शोषण की समस्याएं आज भी समाज को जकड़े हुए हैं, और दिनकर की रचनाएं हमें इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी लेखनी सिखाती है कि सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध निर्भीकता से खड़े होने में है। उनके शब्दों में वह जादुई शक्ति थी, जो तलवार से कहीं अधिक प्रभावशाली थी, क्योंकि वे सत्य और ईमानदारी की स्याही से लिखे गए थे। दिनकर की जयंती हमें यह स्मरण कराती है कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागृत करने, उसे दिशा देने और मानवीय मूल्यों को पुनर्जनन करने का एक अजेय हथियार है। 'दिनकर' का जीवन और उनकी रचनाएं इस सत्य का अमर प्रमाण हैं।

नास्तिक | ओशो

फ्रांस के एक बहुत बड़े मनसविद कुए ने इस नियम को 'लो आफ रिवर्स इफेक्ट' कहा है, उल्टे परिणाम का नियम। जो आप चाहते हैं, उससे उल्टा हो जाता है। आपके चाहने के कारण ही उल्टा हो जाता है। और हमारी पूरी जिंदगी इसी नियम से भरी हुई है। सुख चाहते हैं, दुख मिलता है। सफलता चाहते हैं, असफलता हाथ लग जाती है। जीतना चाहते हैं, हार के सिवाय कुछ भी नहीं होता! हर जगह जो हम चाहते हैं, उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। और प्रार्थना भी करते हैं कि हे परमात्मा, क्या भूल हो रही है, कौन सा कसूर है; कौन से कर्म का फल है कि जो भी मैं चाहता हूं, वह नहीं होता है और उल्टा हो जाता है! और जो मैं कभी नहीं चाहता, वह हो जाता है! और जो मैं सदा चाहता हूं और जिसके लिए श्रम किया हूं, वह नहीं हो पाता! इस नियम को ठीक से समझें। जब भी आप अस्तित्व के सामने अपनी चाह रखते हैं, तभी आप उसके विपरीत हो जाते हैं। अस्तित्व की मर्जी के खिलाफ आप कुछ भी करेंगे, उसमें हारेंगे और टूटेंगे। और सभी चाह उसके खिलाफ है। ऐसी कोई चाह नहीं है, जो अस्तित्व के खिलाफ न हो। होगी ही। हम तो परमात्मा से भी प्रार्थना करते है मंदिर में, उसके ही खिलाफ। घर में कोई बीमार है, हम परमात्मा से कहते हैं कि इसे ठीक कर दे। अगर परमात्मा ही सब कुछ करता है, तो यह बीमारी भी उसके द्वारा है। और जब हम कहते हैं कि इसे ठीक कर दे, तो हम यह कह रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं और तूने हमसे सलाह क्यों नहीं ले ली इस आदमी को बीमार करने के पहले। इसे बदल दे। जो है, उसका हमें स्वीकार नहीं है। और ध्यान रहे, जो है, उसका जब तक हमें स्वीकार नहीं है, तब तक जो भी हम चाहेंगे, उससे उल्टा होगा। और जिस दिन जो भी है, उसका हमें पूरा स्वीकार है तो इस स्वीकार को ही मैं आस्तिकता कहता हूं। आस्तिकता का अर्थ ईश्वर को मान लेना नहीं है, क्योंकि ईश्वर को बिना माने भी कोई आस्तिक हो सकता है। और ईश्वर को मानते हुए भी लाखों लोग नास्तिक हैं, करोड़ों लोग नास्तिक हैं। आस्तिकता का अर्थ है: सर्व स्वीकार का भाव जो है, उसके साथ राजी होना। जैसे मुर्दा नदी में बहता है जहां नदी ले जाए, तो नदी उसे खुद ऊपर उठा लेती है। और जिस दिन कोई व्यक्ति इस अस्तित्व में मुर्दा की भांति हो जाता है, जहां ले जाए यह अस्तित्व, उस दिन यह अस्तित्व खुद उसे उठा लेता है।

रीडर्स मेल

खो दिया बेहतरीन कलाकार

असम ने एक ऐसा कलाकार खो दिया, जिसकी आवाज केवल संगीत नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कृति और संवेदनाओं का प्रतीक थी। जुबिन गर्ग का नाम सुनते ही हर असमिया के मन में गर्व और प्रेम की लहर दौड़ जाती थी। उनकी गायकी में जो आत्मीयता और गहराई थी, वह केवल सच्चे कलाकार की देन थी। उनकी मृत्यु ने संगीत प्रेमियों को गहरे सदमे में डाल दिया। जुबिन केवल एक कलाकार नहीं थे, बल्कि हर असमिया के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत थे। उनके चाहने वालों के लिए यह सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव और आत्मीयता का खो जाना है जिसे जुबिन ने अपने गीतों और मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदान किया। जुबिन गर्ग ने हमें यह सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्मा और संस्कृति का प्रतिबिंब है। असम ने एक सितारा खो दिया, लेकिन जुबिन गर्ग का संगीत हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनका जीवन और उनके गीत हमें हमेशा यह याद दिलाएंगे कि कला और भावनाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। जुबिन गर्ग की विरासत सिर्फ संगीत में ही नहीं, बल्कि हर उस दिल में जिंदा रहेगी, जिसने कभी उनकी आवाज सुनी और महसूस की।

समराज चौहान, असम

बिहार चुनाव में बसपा का दांव

बिहार चुनाव के मद्देनजर बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' यात्रा पर हैं। इस यात्रा के माध्यम से बसपा को उम्मीद है कि बिहार में जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन इस तथ्य पर निर्भर करता है कि बिहार का अनुचित जाति, मुस्लिम एवं अति पिछड़ा समाज कितना बसपा की तरफ जाता है। बिहार में करीब 16 उच्च वर्ग, 19 दलित वर्ग, 17 मुस्लिम, 36 अति पिछड़ा वर्ग है और 27 पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग में से 14 अकेले यादव समाज है जो कि बिहार के चुनाव को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता रहा है। यदि बसपा अध्यक्ष बिहार में रैलियां करती हैं तो बसपा को जरूर कुछ फायदा हो सकता है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

भारत ने दिखाया संयम

भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को एक सप्ताह में दूसरी बार पटखनी देकर साफ कर दिया कि क्रिकेट कौशल और संयम दोनों ही उसके पाले में हैं। सुपर 4 के मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा आतिशी प्रदर्शन किया कि गेंदबाज तो क्या पाकिस्तान की उम्मीदें भी बाउंड्री पार उड़ गईं। इस ताबड़तोड़ खेल से भारतीय टीम की काबिलियत दुनिया ने फिर देखी। उधर पाकिस्तान की टीम हार के डर से खिसिया गई और मैदान पर ओछे व्यवहार की झलक दिखा दी। खेल के मंच पर शालीनता और जज्बे की बजाय पाक खिलाड़ियों की हरकतों से माहौल युद्ध सा हो गया। हार का सामना करने की बजाय खीज और झुंझलाहट परोसना उनकी आदत बन चुकी है। भारत न केवल खेल के स्तर में बल्कि आचरण में भी पाकिस्तान से कई कदम आगे है। यही संतुलन उसे एशिया कप का प्रबल दावेदार बनाता है। पाकिस्तान को समझना होगा कि क्रिकेट में जीत से बड़ी चीज है खेल भावना है और वही उनके पाले से गायब है। इसलिए पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया फादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-हरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

वर्ष - 20, अंक 6783

आर.एन.आई. नं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

किसी देश के नागरिकों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को ही नकारना है।

-नेल्सन मंडेला

बढ़ता समर्थन

इस्राइल-हमास संघर्ष के बीच फलस्तीन की पहचान का मुद्दा फिर जोर पकड़ रहा है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को मान्यता दे दी है, जबकि कई दूसरे देश कतार में हैं। जमीन पर भले इस कदम से फलस्तीन की मौजूदा स्थिति न बदले, पर कूटनीतिक नजरिये से यह बहुत बड़ा शिफ्ट है।

फ़लस्तीन को मान्यता

अमेरिका की नाराजगी । कनाडा और ब्रिटेन G7 समूह का हिस्सा हैं। पहली बार इस समूह के सदस्य देशों ने फलस्तीन को मान्यता दी है और इस कतार में फ्रांस भी है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद वॉशिंगटन के सहयोगी देश अगर फलस्तीन मुद्दे का साथ दे रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह गाजा के मौजूदा हालात हैं।

गाजा का संकट । हमास-इस्राइल संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा में 65 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। लाखों लोग भुखमरी और विस्थापन झेल रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी यह है कि संघर्षविराम की कोई सूरत नजर नहीं आ रही और इस्राइल के नए ग्राउंड एक्शन से हालात और खराब हो गए हैं। हाल में कतर की राजधानी दोहा में इस्राइल के हवाई हमलों से भी बेचैनी बढ़ी और शांति की उम्मीदें धुंधली हो गईं।

वादा पूरा हो । इस्राइल-फलस्तीन विवाद एक सदी से भी ज्यादा समय से सुलग रहा है। 1917 के Balfour Declaration में यहूदियों के लिए फलस्तीनी जमीन पर एक 'घर' बनाने का वादा था, पर उसमें यह भी वादा था कि वहां रह रहे दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 1948 में इस्राइल बनने के बाद से विभिन्न वजहों से वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। एक आबादी को तो अपना देश मिल गया, लेकिन दूसरी आबादी अब भी बिना किसी पहचान के जी रही है।

समाधान का रास्ता । इस्राइल के अस्तित्व में आने से पहले ही दो राष्ट्र का सिद्धांत जन्म ले चुका था - एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। इस विवाद का यही सबसे बेहतर हल भी दिखता है। लाखों लोग जो दशकों से युद्ध की मार झेल रहे, अपने घरों से बेदखल हैं, और जो क्रूर जियो-पॉलिटिक्स का मोहरा बन कर रह गए हैं - उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। भारत भी टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है।

भारत का रुख । पिछले कुछ बरसों में इस्राइल की तरफ भारत का झुकाव ज्यादा दिखा है। संयुक्त राष्ट्र में कई बार उसने इस्राइल-फलस्तीन मामले से दूरी बनाए रखी। लेकिन, पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में टू स्टेट सॉल्यूशन पर मतदान हुआ तो भारत ने इसके समर्थन में वोट दिया। यह सही अप्रोच है।

केंद्र को आधुनिक टेक्नॉलजी में निवेश के लिए 50 हज़ार करोड़ का फंड बनाना चाहिए

भारत के लिए यह आपदा में अवसर है

टीवी मोहनदास पाई & निशा होल्ला

डॉनल्ड ट्रंप ने 21 सितंबर से हर नए H-1B आवेदन पर 1 लाख डॉलर (88 लाख रुपये) की फीस लगा दी। इरादा साफ है। वह नहीं चाहते कि हाई-स्किल्ड विदेशी प्रतिभाएं अमेरिका आएं। इस फीस से उद्योगों या कंपनियों को छूट देने का अधिकार होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव को दिया गया है यानी अमेरिका इस मामले में अपनी मनमानी करेगा।

अमेरिकी कंपनियां आगे । अमेरिका की दलील है कि विदेशी लोग स्थानीय लोगों की तुलना में कम वेतन पर काम करते हैं। लेकिन तथ्य इसके उलट हैं। अमेरिका की एमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐपल, मेटा और इंटेल H-1B की सबसे बड़ी स्पॉन्सर हैं। वैश्विक और भारतीय कंसल्टिंग कंपनियां भी इसमें आगे हैं।

सस्ता नहीं श्रम । ये कंपनियां अपने H-1B वीजा वाले एंप्लॉयीज को सालाना 100,000-200,000 डॉलर यानी 88 लाख से 1.76 करोड़ रुपये देती हैं। यह अमेरिका की प्रति परिवार औसत आय से काफी अधिक है। भारतीय कंसल्टिंग कंपनियां अमेरिकी क्लाइंट से एक व्यक्ति के लिए सालाना 150,000-200,000 यानी 1.32-1.76 करोड़ रुपये लेती हैं। फिर ये एंप्लॉयीज सस्ते कैसे हुए।

भारतीय फर्म्स का हाल । अब भारतीय IT सेवा (TCS, इंफी, विप्रो जैसी) कंपनियां कभी H-1B वीजा पर काफी आश्रित थीं। अब उनके अमेरिकी ऑफिसों में 50-65% स्थानीय लोग काम करते हैं। कोविड के बाद मल्टीनैशनल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर भारत में अपने सेंटर्स में निवेश किया। इन्हें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) कहते हैं। इनमें AI, डिजिटलाइजेशन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में रिसर्च और डिवेलपमेंट हो रहे हैं। कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत में उन्हें बेहतरीन प्रतिभाएं मिल रही हैं। यह सस्ते श्रम की वजह से नहीं हुआ।

US पर बुरा असर । H-1B वीजा

भारी पड़ेगी गलती

- H-1B होल्डर्स सस्ते श्रमिक नहीं
- भारत मे US से और काम आएगा
- डीपटेक के लिए बने फंड

AI image

अमेरिका में दशकों से इनोवेशन की बुनियाद हैं। आज अमेरिका में 1 बिलियन डॉलर से अधिक वैल्यू वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें से आधे के संस्थापक प्रवासी हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल टेस्ला और एनविडिया के संस्थापक भी। ट्रंप अगर इस पर बंदिश लगा रहे हैं तो इसमें US का ही घाटा है।

भारत को लाभ । देश के लिए इससे नया रास्ता खुल सकता है, छोटी अवधि में भले ही भारत को सीमित नुकसान हो। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका से भारत को आउटसोर्सिंग बढ़ सकती है। भारतीय IT कंपनियां पहले ही 90% काम अमेरिका से बाहर के केंद्रों से कर रही हैं। इसे 95% तक ले जाना संभव है। यानी अमेरिका की सख्ती से भारत को फायदा हो सकता है।

सरकार बनाए फंड । भारत को अब आउटसोर्सिंग के बजाय प्रॉडक्ट इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को AI, सेमीकंडक्टर, सिंथेटिक बायॉलजी जैसे deeptech और दूसरे क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ का फंड बनाना चाहिए। सरकार को प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म भी करना चाहिए। अमेरिकी deeptech उद्योगों ने सरकारी डिमांड की बदौलत तरक्की की। वहीं, भारत के स्टार्टअप्स को नौकरशाही के अड़ंगे का सामना करना पड़ता है।

प्रॉडक्ट इनोवेशन । अगर सरकार इन कंपनियों को अपना क्लाइंट बनाती है तो उससे देश में इनोवेशन की क्षमता बढ़ेगी। भारत में प्रतिभा और उद्यमिता की कमी नहीं है। सरकार से उसे निवेश और बाजार चाहिए। अगर नीतिगत समर्थन मिले तो IT कंपनियों ने जिस तरह से भारत को दुनिया का बैकऑफिस बनाया, उसी तरह से यहां से नेक्स्ट जेनरेशन के प्रॉडक्ट लीडर्स भी निकल सकते हैं।

गलत सोच । ट्रंप ने H-1B वीजा के फीस में भारी बढ़ोतरी कर अपने ही देश की कंपनियों के लिए जो मुश्किलें बढ़ाई हैं, उसका आधार बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि अमेरिका में खासतौर पर आधुनिक टेक्नॉलजी में प्रतिभाओं की कमी है। इसी वजह से अमेरिकी टेक्नॉलजी कंपनियों की मांग पर 1990 के दशक में वहां H-1B प्रोग्राम लाया गया था। इसे अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी दी थी। इस बात में भी दो राय नहीं है कि H-1B वीजा प्रोग्राम पर ट्रंप सरकार जिस तरह से बंदिशें लगा रही है, उससे स्थानीय लोगों के लिए वहां ऐसे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर नहीं बढ़ेंगे।

आउटसोर्सिंग बढ़ेगी । अगर सरकार deeptech में निवेश की पहल करती है तो इसका सकारात्मक असर होगा। उसे प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म पर भी ध्यान देना होगा। अगर ऐसा हो पाया तो बहुत कम समय में भारत नेक्स्ट जेनरेशन के प्रॉडक्ट इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

(मोहनदास पाई 3one4 Capital के चेयरमैन हैं और निशा रिसर्च फेलो)

कांटे की बात

AI की दुनिया

हर सेकंड 29 हज़ार मेसेज, AI इस तरह बदल रहा है हमें

ChatGPT जैसे AI चैटबॉट्स ने काम करने का तरीका बदल दिया है। मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और रिसर्च जैसे नॉलेज-आधारित काम अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गए हैं।

70 करोड़ यूजर

2022 में लॉन्च हुए ChatGPT को 70 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हर 10 में से एक वयस्क यूजर है। OpenAI के साथ हार्वर्ड और ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, हर सेकंड करीब 29 हजार मेसेज ChatGPT पर भेजे जा रहे हैं।

सलाह से गाइडेंस तक

40% यूजर्स आर्टिकल लिखने या ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 29% चैट्स सलाह या गाइडेंस के लिए होती हैं, 24% लोग किसी जरूरी जानकारी की तलाश में आते हैं, जबकि तकनीकी यानी प्रोग्रामिंग से जुड़े मेसेज सिर्फ 4.2% हैं।

महिलाएं ज्यादा एक्टिव

शुरुआत में ChatGPT के 80% यूजर पुरुष थे, लेकिन जुलाई 2025 तक महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से भी आगे निकल गई। सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर 18 से 25 साल के युवा हैं, जो कुल चैट्स का 46% भेजते हैं।

प्रस्तुति: प्रदीप तिवारी

मीम बहार

10 वाला बिस्कुट अब कितने का दिया भाई?

ऐवें कुछ भी

वो क़ाग़ज की कश्ती

मैं मॉनसून से बहुत नाराज हूं। उतना ही मैं अपनी किस्मत से नाराज हूं। मैं जिस काम को एन्जॉय करने लगता हूं उसी समय हालात बदल जाते हैं। बस हफ्ते भर पहले मैं बचपन की वो कागज की कश्तियां बनाने लगा था। भूल गया था, पड़ोस में रहने वाले चिंटू ने मुझे अपनी कॉपी के पेज फाड़कर फिर से कश्तियां बनाना सिखाया था।

आलोक सिंह भदौरिया

इस बार मॉनसून जमके बरसा। अखबार वाले कह रहे थे कि पिछले कई सौ साल का रेकॉर्ड टूटा है। वैसे वो हर बार ऐसा कहते हैं। पूरी गली में तरह-तरह के गड्ढे बने हुए थे। बारिश के पानी में से कोई बना दरिया, कोई समंदर। मैं बाइक से चलने में डरने लगा था। पैदल चलकर जाता था। गली पार करने जैसा बोरिंग काम भी रोमांचक बन गया था। मतलब रपटे शर्मा जी के घर के सामने तो सीधे सिंह साहब के मेन गेट पर सिर के बल लैंड करते थे। 100 मीटर पलक झपकते पार। दिल में रोमांच और हड्डियों में दर्द लिए घर को लौटते थे। गली पूरा एडवेंचर पार्क बन चुकी थी। बीच में खुले गटर से बचना भी होता था। पर तीन दिन से बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग बता रहा है मॉनसून विदा हो गया।

बदनाम लड्डू के सामने वाली गली में लोगों ने गड्ढों में चार ट्रॉली मिट्टी डलवा ली थी। वे वहां बारिश के पानी से बने कीचड़ में स्पेन के टोमैटिना महोत्सव की तरह कीचड़पटकी खेलने वाले थे। सब पर पानी फिर गया मतलब पानी सूख गया। अब धूल उड़ रही है। गली जो मटमैले पानी से गुलजार थी अब चांद के सूखे गड्ढों वाली सतह बनी हुई है। कोई कह रहा है सरकार शहर के गड्ढे भरने के लिए कमर कस चुकी है। मैं सरकार के इस तानाशाही भरे कदम का विरोध करता हूं। मुझे ये गड्ढे ऐसे ही चाहिए।

इन गड्ढों में लुढ़क कर घायल होते बच्चे, रपटती बाइक, उछलकर अपने शॉकर खराब करती कारें ... ये सब न होगा तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे... ठेकेदारों, डॉक्टरों से लेकर कार और बाइक मैकेनिक तक। और मैं अपनी कागज की कश्तियां कहां चलाऊंगा।

बोल वचन

राहुल पाण्डेय

चले कटक उपवास

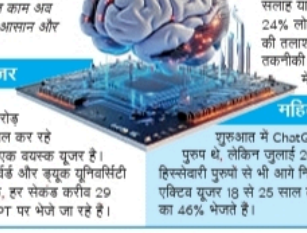

नवरात्र लग गए हैं। घर-घर उपवास चल रहे होंगे। भूख से भरे इन्हीं दिनों में दादी एक कहावत कहती थीं- कबहूं पांड़े घिउ-पूरी, कबहूं कटक उपास। यानी, ब्राह्मण को कभी घी-पूरी खाने को मिलती है तो कभी कठिन उपवास भी करना पड़ता है। इसमें आए शब्द कटक को वो कठिन के रूप में प्रयोग करती थीं। वैसे अवधी में यह लड़ाई-झगड़ा भी है। कटक ओडिशा में तो है ही, आल्हखंड में वर्णित एक अलग शहर भी है। कुमाउंनी में कटक मतलब झगड़ा, आक्रमण, लड़ाई, कटा हुआ टुकड़ा, फीकी चाय पीते समय गुड़, मिस्री या मिठाई का टुकड़ा, चोट या कद्दू की ध्वनि भी है। कमोबेश इन्हीं अर्थों के साथ यह शब्द गढ़वाली में भी मिल जाता है। बुंदेली में कटक यानी दांते के बनाने का शब्द, कलह, लड़ाई, सेना और पहाड़ के बीच का स्थान भी है। ब्रज में कटक या कटक्क का अर्थ सेना, शिविर, छावनी तो होता ही है, समुद्री नमक, घास की चटाई, चक्र और हाथी के दांत पर जड़े हुए पीतल के बंद भी होता है। हिंदी में कटक के अन्य अर्थ हैं- स्वर्ण, पहिया, जंजीर की कड़ी और समुद्र। जाहिर है, कटक के इतने सारे अर्थों को किसी एक शब्द में पिरोने में इंग्लिश क्या, किसी भी भाषा के दांत किटकिटाने लगेंगे!

AI image

स्त्रियों की मौन शक्ति गढ़ रही भविष्य

किरण मजूमदार-शॉ

जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो हमें उनकी यह प्रतिज्ञा याद आती है कि महिलाओं की पूरी भागीदारी के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। उनका 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान एक गहरी सचाई को दर्शाता है। यह मानना कि महिलाओं का स्वास्थ्य ही हमारी राष्ट्रीय प्रगति की नींव है, भारत की विकास यात्रा का मुख्य आधार है।

केंद्र में महिलाएं । प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, खेतों और बायोटेक स्टार्टअप्स में उनके मौन लेकिन प्रभावशाली कार्य हमारे भविष्य को गढ़ रहे हैं। उन 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें, जो भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ हैं। ऐसे ही ICMR, NIV और AIIMS की महिला वैज्ञानिकों पर विचार करें, जिन्होंने 2020 में SARS-CoV-2 वायरस को अलग करने में मदद की और भारत के स्वदेशी टीकों का मार्ग प्रशस्त किया।

स्टार्टअप्स की अगुआई । भारत की 62.9% महिला कार्यकर्ता कृषि में हैं। इनमें से कई को सूखा-रोधी व फसल सुरक्षा जैसे बायोटेक

कॉमन रूम

AI image

समाधान अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। बायोटेक उद्यमिता में भी महिलाएं सस्ते डायग्नोस्टिक, जीनोमिक्स और वैक्सीन नवाचार जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की अगुआई कर रही हैं।

नीतिगत और संस्थागत समर्थन । महिलाओं की क्षमता को उभारने में सरकारी पहल निर्णायक रही है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'मिशन शक्ति' हो, संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम हो या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया हकीकत यह है कि महिला-प्रधान विकास की मजबूत रूपरेखा तैयार हो चुकी है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार । विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय महिलाएं सचमुच सितारों तक पहुंच रही हैं। इसरो में महिलाओं ने चंद्रयान-2 और मंगलयान जैसे मिशनों में निदेशक की भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत, STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी के मामले में दुनिया में अग्रणी है।

भविष्य की ओर । विज्ञान-आधारित विकास का भविष्य उन महिलाओं द्वारा गढ़ा जाएगा जो जीनोमिक्स, मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स, बायोलॉजिक्स और सटीक उपचार को आगे बढ़ाएंगी। एक गैराज लैब से लेकर एक वैश्विक बायोलॉजिक्स कंपनी बनाने तक की मेरी अपनी यात्रा ने मुझे सिखाया है कि नवाचार जमीनी स्तर से जन्म लेता और मेहनत व धैर्य से आगे बढ़ता है।

अहम मोड़ । प्रधानमंत्री की दृष्टि स्पष्ट है- महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि इस भविष्य की सह-निर्माता के रूप में देखा जाना चाहिए। समय आ गया है, सभी क्षेत्रों में नेतृत्व सुनिश्चित करे कि महिला वैज्ञानिक, स्वास्थ्य-कर्मी और उद्यमी पूरी तरह से दिखाई दें। जब ऐसा होगा, तो भारत न केवल अपना वादा पूरा करेगा बल्कि दुनिया की उम्मीदों से भी आगे बढ़ जाएगा।

(लेखिका बायोकॉन की एक्जीक्युटिव चेयरपरसन हैं)

बिहार में क्या कांग्रेस खेल बदलेगी

नरेन्द्र नाथ

क्या इस बार बिहार में I.N.D.I.A. की तरफ से कांग्रेस मैच फिनिशर की भूमिका निभा पाएगी? क्या इस बार RJD के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस अपनी अहमियत साबित कर पाएगी? इन्हीं दो सवालों के बीच इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में I.N.D.I.A. का भविष्य छिपा हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा को मिले रेस्पॉन्स के बाद गठबंधन के दलों में उम्मीदें जगी हैं कि कांग्रेस इस बार चुनाव में ऐसा प्रदर्शन करेगी, जो अंतिम नतीजे को प्रभावित करेगा।

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

जीत-हार का गणित

I.N.D.I.A. में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सारा दारोमदार इसलिए भी माना जा रहा है, क्योंकि 2004 से अब तक RJD अकेले दम चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा है। 2015 में पार्टी बड़ी जीत के साथ तब सत्ता में आई, जब नीतीश कुमार और कांग्रेस दोनों ने हाथ मिलाया था। इसके बाद 2020 में नीतीश गठबंधन से अलग होकर BJP के साथ NDA का हिस्सा हो गए। तब कांग्रेस 243 सीटों में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र 19 सीटें ही जीत सकी। दूसरी ओर, RJD ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीती थीं। तब एक वर्ग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके खराब प्रदर्शन के कारण ही महागठबंधन सरकार नहीं बना सका था। हालांकि कांग्रेस का तर्क था कि उसे चुन-चुन कर ऐसी सीटें दी गई थीं जो बेहद कठिन मानी जाती थीं। इसके बाद 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस ने RJD से बेहतर प्रदर्शन किया।

अब I.N.D.I.A. इन पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए मैदान में उतरने का दावा कर रहा है। लेकिन राज्य में पिछले कई सालों से कांग्रेस का अपना वजूद नहीं रहा है। पार्टी अधिकतर समय RJD के साथ ही गठबंधन में रही और जब भी अकेले लड़ी, तब कोई छाप नहीं छोड़ पाई। हालांकि इसी राज्य में पार्टी ने आजादी से लेकर 1990 तक अधिकतर समय राज किया था। पार्टी की हालत हाल के समय में इतनी खराब हुई कि तमाम नेता दूसरी पार्टी में चले गए। उसका अपना कोई जनाधार या वोट बैंक भी नहीं रहा। यही कारण है कि कांग्रेस किस स्तर तक गठबंधन को लाभ पहुंचा पाएगी, इस पर हमेशा सवालिया निशान रहे।

इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन करना I.N.D.I.A. के लिए जरूरी इसलिए भी है कि पिछले कई सालों से RJD एक निश्चित वोट संख्या से आगे नहीं जा पाया है। 2020 में इस मिथ को तेजस्वी यादव मुस्लिम-यादव समीकरण से तोड़ने में सफल तो हुए, लेकिन अंततः वह नाकाफी साबित हुआ। I.N.D.I.A. के रणनीतिकारों के अनुसार अगर कांग्रेस मुस्लिम-यादव के बाहर कोई वोट लाने में सफल रही, तो फिर चुनाव में वह गेमचेंजर होगा। ऐसे में सबसे अधिक नजर दलित वोटों पर है।

M-Y से आगे

अगर कांग्रेस बेहतर करती है तो I.N.D.I.A. सरकार बना सकता है। दरअसल, M-Y यानी मुस्लिम-यादव का RJD वोट बैंक राज्य के तीस फीसदी से अधिक वोट कवर करता है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। सत्ता की चाबी वहां है, जहां RJD पिछले कई सालों से सेंध नहीं लगा सका है। इस चुनाव में उस चाबी को खोजने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास रहेगी। पार्टी की शीर्ष स्तर की मीटिंग इसी हफ्ते पटना में होने वाली है। इसके बाद राहुल और प्रियंका कई बार बिहार दौरा करने वाले हैं। ऐसे में I.N.D.I.A. को लगता है कि इसका लाभ मिलेगा और RJD भी इस बार कई बाधाएं पार कर लेगा।

साधना और संयम का प्रतीक है देवी का दूसरा स्वरूप

निर्मल जैन

शारदीय नवरात्र का पावन पर्व देवी भगवती के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना का समय है, जो हमें आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर ले जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब राक्षसों के अत्याचार से देवता त्रस्त हो गए, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए शक्ति की आराधना की। शक्ति ने दुर्गा के रूप में प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया और देवताओं की रक्षा की। इन नौ दिनों में देवी के नौ स्वरूपों- शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं।

नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। उनका नाम ही बताता है कि वह ब्रह्मचर्य और तपस्या का आचरण करने वाली देवी हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की उत्पत्ति पार्वती के रूप में हुई, जब उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनका यह रूप तप, साधना और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। उनकी उपासना से भक्तों को मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह दिव्य शक्ति हैं, जो कठोर तपस्या, संयम और ज्ञान के माध्यम से जीवन को उज्ज्वल बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का रूप साधना और आत्म संयम का प्रतीक है, जो हमें मन की अशांत प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। नवरात्र की आध्यात्मिक यात्रा तीन चरणों में बंटी है - तामसिक, राजसिक और सात्विक। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तामसिक से राजसिक यात्रा के संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, जब मन संयम और तपस्या से पूर्ण होता है और आत्मशक्ति जागृत होती है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने अंदर के विकारों जैसे क्रोध, मोह, और अहंकार से लड़ने की तैयारी करता है। और देवी के इस स्वरूप की आराधना से उसके अंदर आत्मशक्ति जागृत होती है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को शक्ति, धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो उनके जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाती है। यह आराधना हमारे मन, बुद्धि और आत्मा के शोधन का माध्यम बनती है, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी के प्रति समर्पण हमें अपने भीतर छिपे रावण रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्ति मिलती है। यही असली नवरात्र है, जब हम जागरूक होकर सच्चे अर्थों में अपने अंदर बदलाव लाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं।

ब्रह्मचारिणी केवल तपस्विनी देवी नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की मार्गदर्शिका हैं, जिनकी आराधना से हम जीवन में सच्चा सामर्थ्य और शांति प्राप्त करते हैं।

भूल सुधार

▸ विदेश नीति में चुनौतियां

22 सितंबर के अंक में प्रकाशित संपादकीय, जिसकी हेडलाइन 'विदेश नीति में चुनौतियां' है, इसमें एक सब-हेडिंग 'पाक-यूएई समझौता' लिखा है, जबकि इसकी जगह 'पाक-सऊदी समझौता' होना चाहिए। भारत की विदेश नीति में आई हालिया दुश्वारियों पर लिखे गए इस संपादकीय में हुई गलती की ओर हमारा ध्यान आज कुछ सुधी पाठकों ने दिलाया। हम इस भूल के लिए क्षमाप्रार्थी हैं। इसके लिए शुक्रगुजार भी कि पाठकों ने हमारा ध्यान इस भूल की तरफ दिलाया।

दैनिक जागरण

शरीर भी एक मंदिर है और उसकी देखभाल एक उपासना

उपभोक्ता और उद्योग

जीएसटी में सुधार के तहत जो रियायत दी गई, उस पर अमल शुरू हो गया और प्रधानमंत्री ने इस अवसर को बचत उत्सव की संज्ञा दी। उन्होंने लोगों से यह अपील भी की कि वे स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदें। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन क्या हमारे उद्योग उपभोक्ताओं की जरूरत की सभी वस्तुओं का निर्माण कर पा रहे हैं और क्या उनकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय है? इन प्रश्नों के समक्ष है हमारा उद्योग जगत। उसके कारण ही चीनी वस्तुओं पर निर्भरता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और चीन के साथ व्यापार घाटा कम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी की राह पर चलने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की बातें अभी की जा रही हैं। इन बातों पर कोविड महामारी के दौरान ही बल दिया जाने लगा था, लेकिन नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं निकले। इसका मुख्य कारण है भारतीय उद्योग जगत की शोध एवं विकास के प्रति अनिच्छा। शोध एवं विकास के अभाव में ही वह वैसे नवाचार नहीं कर पा रहा है, जैसे अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां करती हैं और जिनमें हमारे युवाओं को नौकरियां पाने में आसानी होती है। शोध एवं विकास का अभाव तब है, जब बड़े उद्योगों के पास धन की कहीं कोई कमी नहीं।

यह चिंता की बात है कि भारतीय उत्पाद विश्व बाजार में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। यदि भारतीय उद्योग जगत विश्व बाजार में अपना स्थान नहीं बना पाएगा तो फिर भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भरता का यह अर्थ नहीं कि भारत में निर्मित वस्तुएं केवल भारत में ही बिकें। दुर्भाग्य से अभी तो अनेक ऐसी वस्तुएं जो देश में आसानी से निर्मित हो सकती हैं, उन्हें आयात करना पड़ रहा है। इसका एक कारण आयातित वस्तुओं का सस्ता होना भी है और भारत में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता संतोषजनक न होना भी। यह तकनीक का युग है और भारतीय युवाओं की तकनीकी दक्षता किसी से छिपी नहीं, लेकिन उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर विदेश में दिखते हैं। आखिर भारतीय कंपनियां उन्हें देश में ही रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम क्यों नहीं? यदि वे ऐसा कर पातीं तो शायद अमेरिका की ओर से एच-1बी वीजा फीस में अप्रत्याशित वृद्धि चिंता और अनिश्चितता नहीं पैदा करती। सरकार एक लंबे समय से भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खरा उतरने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। यह सही समय है कि सरकार उन कारणों का पता लगाए, जिनके चलते हमारे सक्षम उद्योग भी शोध एवं विकास की राह नहीं पकड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी तंत्र में कुछ ऐसी खामियां हैं, जिनके चलते उद्योग जगत अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने में आनाकानी कर रहा है।

सड़कों का विकास

सड़कें किसी भी राज्य के विकास का आईना होती हैं। हरियाणा में लंबे समय से टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा उत्थान योजना का शुभारंभ किया जाना सराहनीय है। ग्रामीण परिवेश की सड़कों की स्थिति अति दयनीय होने के कारण इनपर चलना भी कठिन है। कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है कि आवागमन के लिए लंबी दूरी तय करने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे समय तो खराब होता ही है, आर्थिक खर्च भी बढ़ता है। सड़कों में गहरे गड्ढों के कारण हादसों मे बेतहाशा वृद्धि होना चिंतनीय है। मुख्यमंत्री की ओर से राज्यभर में 400 से अधिक सड़कों की मरम्मत एवं सुधार की घोषणा से बदतर हो चुकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा और आवागमन सुगम हो जाएगा। गांवों से शहरों तक पहुंचने में समय कम लगेगा और हादसों में भी कमी आएगी। साथ ही लंबे समय से झेलनी पड़ रही परेशानी से भी राहत मिलेगी। सड़कों के शिलान्यास अवसर पर मुख्यमंत्री की ओर से ठेकेदारों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को चेताया जाना कई मायनों में सही है। सड़कों की गुणवत्ता पूरी तरह ठेकेदारों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। इनका तथाकथित गठजोड़ सड़कों पर चलने वालों की समस्याएं तो बढ़ाता ही है, सरकार को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाता है। निर्माण के दौरान सही इंजीनियरिंग नहीं होने से जलजमाव एवं अन्य परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। किसी भी हाल में सड़कों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। कोई दोराय नहीं कि सड़कें अच्छी और सुगम होंगी तो विकास की गति भी तेज होगी और जीवन-स्तर में सुधार भी होगा।

> सड़कों की दशा सुधारने के लिए उत्थान योजना आरंभ करने से प्रदेश के विकास को अवश्य गति मिलेगी

असाधारण शौर्य की अप्रतिम गाथा

जगतवीर सिंह

साठ साल बाद भी 1965 का युद्ध इसलिए प्रासंगिक है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरा नहीं है

इतिहास में वर्तमान और भविष्य के लिए भी सूत्र छिपे होते हैं। हमारे इतिहास का ऐसा ही एक हिस्सा 1965 है। उस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच पहला औपचारिक युद्ध हुआ था। आज 23 सितंबर को उस युद्ध के पूरे साठ वर्ष बीत गए हैं। इससे पहले आजादी के तुरंत बाद भारत ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया था। हालांकि 1962 में चीन के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर है, क्योंकि उस लड़ाई ने भारत की रक्षा तैयारियों, खुफिया जानकारी और राजनीतिक नेतृत्व एवं सेना के बीच समन्वय में गंभीर खामियों को उजागर किया था। इसके अलावा, पाकिस्तान ने 1963 में शक्सगाम घाटी चीन को सौंपकर ड्रैगन के साथ संबंधों को मजबूत किया। चीन ने अगले ही साल अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया। उसी दौरान पाकिस्तान सीईएनटीओ और एसईएटीओ जैसे संगठनों का हिस्सा बन रहा था। इनमें सीईएनटीओ एक सैन्य गठबंधन था। इसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और ब्रिटेन शामिल थे। जबकि एसईएटीओ दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद को रोकने के उद्देश्य से बना गठबंधन था, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाइलैंड और पाकिस्तान शामिल थे। ये दोनों संगठन शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी विस्तारवाद के जवाब में बनाए गए थे। इनका हिस्सा बनकर पाकिस्तान की ताकत बढ़ी थी।

प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पाकिस्तान को लगा कि पहले से सैन्य रूप से पस्त दिख रहा भारत राजनीतिक नेतृत्व में भी कमजोर पड़ गया है। मौका देखकर फरवरी 1965 में उसने आपरेशन डेजर्ट हाक शुरू किया। इस सैन्य अभियान के जरिये पाकिस्तान भारतीय सीमा से लगी चौकियों पर हमला करके कच्छ के रण पर नीयत खराब किए हुए था। भारत ने जवाब में आपरेशन एब्लेज का आगाज किया। इसी दौरान भारत ने कारगिल में पाइंट 13,620 की एक रणनीतिक चोटी पर कब्जा कर लिया। यह श्रीनगर से लेह तक को नियंत्रित करती थी। इस संदर्भ में ब्रिटेन की मध्यस्थता में एक जुलाई को कच्छ समझौता हुआ, जिसमें भारत को कारगिल में जीते गए क्षेत्रों को खाली करने के लिए मजबूर किया गया। महीने भर बाद ही पाकिस्तान ने 5 अगस्त को आपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जो उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ। इसके तहत पाकिस्तान ने हजारों सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजा ताकि कश्मीरियों को भड़काया जा सके, लेकिन उसका यह आकलन गलतफहमियों पर आधारित था। कश्मीरी तो विद्रोह के लिए नहीं खड़े हुए, उलटे लेफ्टिनेंट जनरल हरबक्श सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी कमान ने कारगिल, तिथवाल और हाजी पीर में रणनीतिक क्षेत्रों पर अपनी बढ़त बनाकर घुसपैठ की गुंजाइश ही खत्म कर दी।

पाकिस्तान ने इसके बाद आपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत में प्रवेश कर छंब पर कब्जा करना था। पाकिस्तान ने बिना कोई कारण बताए अपने डिवीजन कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को उनके पद से हटाकर अयूब खान के पसंदीदा मेजर जनरल याह्या खान को नियुक्त किया। भारत ने उस दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार एक मोर्चा खोला। 11 कोर के तहत आपरेशन रिडल ने लाहौर की ओर आक्रमण शुरू किया। इस दौरान डोगराई को कब्जे में भी लिया गया। अमृतसर को भारत से काटने के पाकिस्तानी मंसूबों पर भी भारत ने पानी फेर दिया। इसी युद्ध में आसल उत्ताड़ (सियालकोट के पास) की लड़ाई में अद्भुत शौर्य दिखाने वाले अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी जीप से पाकिस्तान के पैटन टैंकों को ध्वस्त किया, जो उस समय अजेय माने जाते थे।

निःसंदेह उस युद्ध से कई सबक मिले, लेकिन साठ साल बाद भी उसके सबक प्रासंगिकता लिए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, नैरेटिव को तोड़ना-मरोड़ना, क्षेत्रीय विवादों की प्रासंगिकता और बाहरी शक्तियों की भूमिका विभिन्न रूपों में वैसी ही बनी हुई है। इस दौरान युद्धों की प्रकृति भी बदल गई है। 1947-48 और 1962 में भारतीय सेना ने वायु सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, जबकि 1965 में नौसेना की भूमिका सीमित थी और इसे सीमा पार करने की अनुमति नहीं थी। 1971 में तीनों सेवाओं का उपयोग किया गया, लेकिन पूरा ध्यान पूर्वी मोर्चे पर था। उसमें पश्चिमी मोर्चे को भारत के लिए मुख्य रूप से होल्डिंग एक्शन के रूप में देखा गया। कारगिल (1999) संघर्ष घुसपैठ के संदर्भ में 1965 के साथ समानता लिए था, लेकिन लड़ाई एक विशेष क्षेत्र तक सीमित थी, जिसमें नियंत्रण रेखा को पार करने का कोई संदर्भ नहीं था। हाल के आतंकी हमलों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर देश के समक्ष सुरक्षा चुनौतियों की निरंतरता को ही दर्शाते हैं। इस बीच गलवन जैसा बर्बर संघर्ष भी था। यह स्थिति दर्शाती है कि पड़ोस में बढ़ती नापाक साजिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

देखा जाए तो 1965 का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, अपितु राष्ट्रीय संकल्प था, जहां सैन्य साजोसामान की कमियों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने साहस और दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी। जनभावनाओं से ओतप्रोत इस लड़ाई ने पाकिस्तान को भारी चोट पहुंचाई। 1965 के बाद एक अहम सबक यही मिला कि आत्मनिर्भरता को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसे रक्षा सहयोग, रणनीतिक गठबंधन और उन्नत प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण सामग्रियों की उपलब्धता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 1965 युद्ध के छह साल बाद हमारी सेनाओं ने 1971 में शानदार विजय प्राप्त की। साठ साल बाद आपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर दिखाया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसे विकसित हुई है। इस दौरान नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग व्यापक एवं प्रभावी परिणाम देने वाला रहा है। हमें 1965 के युद्ध को राष्ट्र के संकल्प और उसकी सशस्त्र सेनाओं की क्षमता की एक रणनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहिए।

(लेखक सेवानिवृत्त मेजर जनरल एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया में प्रतिष्ठित फेलो हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी आयुर्वेद

डा. मनमोहन शर्मा

शरीर, मन और चेतना में संतुलन बनाने वाले आयुर्वेद की आवश्यकता आधुनिक जीवनशैली में और अधिक बढ़ गई है

अथर्ववेद में वर्णित आयुर्वेद वह विज्ञान है, जो आयु अर्थात जीवन का ज्ञान देता है। हर वह व्यक्ति जो स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना करता है, उसे आयुर्वेद को जानना एवं अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद न केवल मनुष्य को निरोग रखने पर बल देता है, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का संदेश देता है। आयुर्वेद इसलिए विशिष्ट है, क्योंकि यह शरीर की व्याधियां दूर करने के साथ मन के दोषों का भी निदान करता है। इसीलिए योग और ध्यान भी आयुर्वेद के अंग हैं। मान्यता है कि आयुर्वेद को स्वयं ब्रह्मा जी से भगवान धन्वंतरी और उनके उपरांत विभिन्न ऋषियों एवं महर्षियों जैसे सुश्रुत, चरक आदि द्वारा जनकल्याण हेतु प्रतिपादित किया गया। इसके उद्देश्य को यह श्लोक प्रकट करता है-

स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं
आतुरस्य विकार प्रशमनं च॥

अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग का प्रशमन करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। संपूर्ण ब्रह्मांड पंचमहाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। इसी सिद्धांत पर आयुर्वेद आधारित है। आयुर्वेद की मान्यता है कि ब्रह्मांड हो या सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, सभी का मूल एक ही है। यही पंचमहाभूत शरीर में दोष, धातु एवं मल के रूप में विद्यमान रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में तीन दोष वात, पित्त, कफ माने गए हैं। इन दोषों की समावस्था ही मनुष्य में स्वास्थ्य को परिभाषित करती है। जहां अधिकांश चिकित्सा पद्धतियां विशेषकर पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियां मात्र मनुष्य के शरीर के रोगों को ठीक करने पर केंद्रित हैं, वहीं आयुर्वेद जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इसीलिए उसे संपूर्ण चिकित्सा पद्धति कहा गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग, आहार आदि द्वारा एवं प्रकृति से प्राप्त हानिरहित फल-फूल, जड़ी-बूटी, खनिजों इत्यादि द्वारा चिकित्सा का प्रविधान आयुर्वेद में ही मिलता है।

आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे जीवन में अप्राप्त की प्राप्ति की जाए, प्राप्त का रक्षण किया जाए, रक्षित की वृद्धि की जाए एवं जो वर्जित है, उसका त्याग किया जाए। यही स्वस्थ एवं सुखी जीवन का मूलमंत्र है। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही आयुर्वेद हमारी संस्कृति और जीवनशैली का अभिन्न अंग रहा, पर कालांतर में आक्रांताओं द्वारा भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की प्रवृत्ति एवं दासता की मानसिकता के चलते आयुर्वेद का क्षरण हुआ। इसके उपरांत अंग्रेजी सत्ता में आयुर्वेद को समाप्त करने का प्रयास किया गया और आयुर्वेद को निष्प्रभावी बताकर पश्चिमी चिकित्सा को ही महत्व दिया गया। आयुर्वेद को श्रीहीन करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों, वैद्यों को झोलाछाप अर्थात नकली डाक्टर कहा गया। कोविड महामारी के समय आयुर्वेदिक औषधियां कोरोना वायरस के प्रभाव को समाप्त करने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुईं। इस कारण आयुर्वेद के प्रति पुनः विश्वास एवं रुचि जाग्रत हुई। वर्तमान में भारत सरकार एवं उसकी संस्थाओं द्वारा आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाने के जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उनसे भी आयुर्वेद का प्रभाव और उसके प्रति भरोसा बढ़ रहा है।

आयुर्वेद प्रकृति पर आधारित विज्ञान है। इस कारण प्रकृति का संरक्षण ही आयुर्वेद का संरक्षण है। यह हम सबकी चिंता का विषय बनना चाहिए कि आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग होने वाली वनस्पतियां, खनिज आदि दुर्लभ होते जा रहे हैं या फिर उनकी उपलब्धता कम हो रही है। इन्हें संरक्षित करना आयुर्वेद के लिए एक बड़ी चुनौती है। वन संरक्षकों एवं किसानों को औषधि के रूप में प्रयोग होने वाली वनस्पतियों, पौधों, वृक्षों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसका लाभ केवल आयुर्वेद को ही नहीं, ग्रामीणों और विशेष रूप से किसानों को भी होगा। आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता स्थापित करने के लिए मानक नियमों का पालन भी समय की मांग है। आयुर्वेद की विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए यह भी अनिवार्य है कि आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शोध को प्राथमिकता दी जाए। यह कार्य आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को विशेष रूप से करना होगा। यह प्राथमिकता के आधार पर किया भी जाना चाहिए, क्योंकि मानव को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने वाला विज्ञान यही है। भारत सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि आयुर्वेद की महत्ता विश्व स्तर पर कैसे स्थापित हो।

आयुर्वेद के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए युवाओं में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की भी आवश्यकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विज्ञानसम्मत पद्धति है। अभी अपने देश में जनसंख्या के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में आयुर्वेद चिकित्सक नहीं हैं। लोगों और विशेषकर युवाओं को यह समझना होगा कि मानव स्वास्थ्य की वास्तविक कुंजी आयुर्वेद में निहित है और आत्मा, इंद्रियों एवं मन की प्रसन्नता आयुर्वेद से ही संभव है। आयुर्वेद शरीर, मन और चेतना में संतुलन बनाए रखने का काम करता है और आज की आधुनिक जीवनशैली में इसकी आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। इस आवश्यकता की पूर्ति ही आयुर्वेद दिवस को सार्थक करेगी।

(लेखक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं)

response@jagran.com

संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान है आयुर्वेद। फाइल

ऊर्जा

खुशी

विधाता ने मनुष्य को अधिकाधिक खुश रखने के लिए उसके भीतर चार हार्मोन के स्राव की व्यवस्था की है। ये हैं-डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और आक्सीटोसिन। खुशी के अनुभव का आनंद उसी को हो सकता है, जिसे कभी न कभी नाखुशी या तनाव का अनुभव हुआ हो। ऐसे अनुभव के लिए विधाता ने शरीर में अप्रसन्नता का हार्मोन भी बनाया है, लेकिन इसकी संख्या एक ही है, जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। दुर्भाग्य से आधुनिक भौतिकता प्रधान युग में हममें अनियंत्रित इच्छाओं, स्वार्थपरता, ईर्ष्या और परस्पर प्रतिद्वंद्विता से संबंधित अनेक ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियां घर कर गई हैं, जो हमारे अंदर बार-बार कोर्टिसोल उत्पन्न करती हैं। यह न केवल हममें तनाव उत्पन्न करता है, बल्कि खुशी के हार्मोन के स्राव को बाधित भी करता है।

सकारात्मक मनोभाव और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर हम अपने अंदर खुशी के हार्मोन स्राव को बढ़ा सकते हैं। ऐसे हार्मोन की उत्पत्ति के उपाय अत्यंत सरल हैं। किसी कार्य को पूर्ण करने से जो संतोष मिलता है, उससे डोपामिन का स्राव होता है। अतः हमें किसी दीर्घकालिक लक्ष्य की तुलना में छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इससे एक साथ कार्य का बोझ नहीं पड़ता और बार-बार कार्य पूर्णता की संतोषजनक अनुभूति प्राप्त होती है। हंसमुख माहौल में रहना, संगीत सुनना, व्यायाम करना, टहलना, लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना जैसी आदतें सेरोटोनिन और एंडोर्फिन सक्रिय करती हैं। लोगों से जोशपूर्ण ढंग से मिलने, हाथ मिलाने या आलिंगन करने जैसे व्यवहारों से आक्सीटोसिन में वृद्धि होती है। खुशी से संबंधित हार्मोन को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक सोच एवं स्वस्थ आदतें अपनाकर हम न केवल अपने जीवन में खुशी अनुभव कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं।

डा. अरुण कुमार तिवारी

सौर ऊर्जा में स्वदेशी का संकल्प

रंजना मिश्रा

भारत ने 2028 तक पूर्णतः स्वदेशी सौर विनिर्माण हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सशक्त और निर्णायक कदम है। वर्तमान में भारत अपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर सोलर पैनल और उनके घटकों के आयात पर निर्भर है, विशेषकर चीन से। किसी भी राष्ट्र के लिए ऊर्जा सुरक्षा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग होती है। जीवाश्म ईंधन के आयात पर हमारी अत्यधिक निर्भरता हमें अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस बाजारों की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है। सौर ऊर्जा, जो कि एक अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इस निर्भरता को कम करने का एक स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है। इसके स्वदेशी विनिर्माण से भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह हमें विदेशी शक्तियों के दबाव से मुक्त करेगा और हमें अपनी ऊर्जा नीतियों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की अनुमति देगा। आत्मनिर्भरता का यह कदम हमें वैश्विक ऊर्जा भू-राजनीति में एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा।

> सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है और यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है और यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वदेशी सौर ऊर्जा विनिर्माण को बढ़ावा देने से भारत को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह पहल हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित करने में मदद करेगी। इससे शहरों में वायु प्रदूषण कम होगा, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

वैसे यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन इसे हासिल करने की दिशा में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा हमें अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करने और कुशल श्रमशक्ति तैयार करने की आवश्यकता होगी। सरकार को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनानी होंगी। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ, सब्सिडी और ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

इसके अलावा हमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना होगा, ताकि हम नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठा सकें। हमें इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने और एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है। शिक्षा प्रणाली में सौर ऊर्जा से संबंधित विषयों को शामिल करना भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि भविष्य के लिए एक प्रशिक्षित कार्यबल तैयार हो सके।

(लेखिका तकनीक की जानकार हैं)

मेलबाक्स

आमजन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दें नेता

'सतही विमर्श सफलता की गारंटी नहीं' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में डा. एके वर्मा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। चुनाव प्रणाली में धांधली और वोट चोरी का आरोप लगाने वाले नेता विभिन्न राज्यों में अपनी जीत के बाद चुप्पी क्यों साध लेते हैं? एटम बम-हाइड्रोजन बम फूटने जैसे भारी शब्दों का प्रयोग कर किसी तथाकथित रहस्योद्घाटन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन क्या सच में किसी मुद्दे को इस तरह से व्यक्त करना अतिशयोक्ति और भ्रामक नहीं है? वास्तव में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से हर राजनीतिक दल और उसके नेता भलीभांति अवगत हैं। यदि उनमें कोई संशय होता, तो जिन राज्यों में उनकी पार्टी जीतती, वहां भी होता। असल में वे जनता के मन में संशय पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि ऐसा करने से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है। आत्ममंथन कर अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने के बजाय केवल चुनाव प्रणाली में खामियां ढूंढ़ने से उन्हें चुनावों में सफलता नहीं मिलेगी। देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें उठाने की आवश्यकता है, लेकिन जब विपक्ष जनता के मुद्दों को महत्व देने के बजाय अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो जनता उन पर विश्वास कैसे करेगी? यदि चुनाव प्रणाली को लेकर जनता के मन में संशय उत्पन्न हो गया, तो क्या वे चुनावों में भाग लेने से कतराएंगे नहीं? ऐसा होने पर लोकतंत्र की मजबूती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नेताओं को चाहिए कि वे सतही विमर्श से परे जाकर वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दें और जनता के विश्वास को पुनः स्थापित करें। केवल आरोप-प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें अपने कार्यों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सके और जनता का इसमें विश्वास बना रहे।

लवली सिंह, वाराणसी

विपक्ष की भूमिका

भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका सरकार पर निगरानी रखने और जनता के मुद्दों को उठाने की होती है, लेकिन जब यह भूमिका केवल आरोप, आक्षेप और अपशब्दों तक सीमित हो जाए तो उसका परिणाम उलटा ही निकलता है। हाल के वर्षों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने चुनावी रणनीति के तौर पर फेक नैरेटिव और आक्रामक आरोपों को केंद्र में रखा है। राहुल गांधी का 'वोट चोरी' वाला बयान इसी प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण है। विडंबना यह है कि जिस चुनाव आयोग पर वे सवाल खड़े कर रहे हैं, उसी की प्रक्रिया से कांग्रेस की सरकारें हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में बनी हैं। कांग्रेस को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या केवल फेक नैरेटिव गढ़कर ही जनता को जीता जा सकता है। अमेरिका में ट्रंप ने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' जैसे सकारात्मक नारे पर चुनाव जरूर जीता, लेकिन उनकी साख समय के साथ गिरती चली गई। भारत में भी अब केवल नैरेटिव या आक्रामक प्रचार से जनता प्रभावित होने वाली नहीं। जनता का रुझान अब विकास, स्थिरता और नेतृत्व की विश्वसनीयता की ओर है। जनता अब सतही विमर्श को भांपने लगी है। गाली-गलौज और आरोपों से न तो रोटी-रोजगार की समस्या सुलझती है और न ही विकास की राह निकलती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यदि सचमुच जनता का विश्वास पाना चाहते हैं, तो उन्हें सकारात्मक मुद्दों पर ध्यान देना होगा-जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग। केवल प्रधानमंत्री या सरकार को 'चोर' कह देने से मतदाता का मन नहीं जीता जा सकता। स्पष्ट है कि लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना जरूरी है, लेकिन जब वह व्यक्तिगत हमले और नकारात्मक नैरेटिव का रूप ले लेती है, तो नुकसान विपक्ष को ही होता है। वर्तमान परिस्थितियों में जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है और अब उसे भ्रमित करना आसान नहीं रहा। विपक्ष को यह समझना होगा कि चुनाव जीतने का रास्ता केवल झूठे आरोपों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और विश्वसनीय विकल्प पेश करने से ही निकलता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

77 लाख से अधिक लोग समूचे विश्व में आंतरिक विस्थापन का शिकार हुए आपदाओं के कारण वर्ष 2023 में। जबकि यह संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। अन्य कारणों से होने वाले विस्थापन की संख्या कहीं अधिक है।

आजकल

नाटो में हो रहे बदलाव का एशिया पर असर

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब भी वैश्विक शक्ति संतुलन की चर्चा होती है, नाटो का नाम सबसे पहले आता है। शीतयुद्ध के दौर से लेकर आज तक इसने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। बीते कुछ वर्षों से नाटो का प्रभाव यूरोप से आगे बढ़ते हुए एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक फैल रहा है। हाल में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और सुरक्षा रणनीतियां यह संकेत देती हैं कि भविष्य में नाटो एक वैश्विक सुरक्षा ढांचे का केंद्रीय स्तंभ बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इस परिवर्तन का प्रभाव एशियाई क्षेत्र पर पड़ेगा और भारत के लिए यह अवसरों एवं चुनौतियों का मिश्रण होगा

प्रो. एम. एल. मीणा
विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, हरियाणा केंद्रीय विवि, महेंद्रगढ़

बीते कुछ माह के दौरान नाटो ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो उसकी भविष्य की दिशा और एशियाई प्रभाव को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे उल्लेखनीय निर्णय यह रहा कि सदस्य देशों ने 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का पांच प्रतिशत रक्षा और सुरक्षा खर्चों से जुड़े मद में करने का लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य केवल सैन्य क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आंतरिक सुरक्षा, साइबर स्पेस, अवसंरचना और आपदा प्रबंधन जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। साथ ही, रूस द्वारा पोलैंड और रोमानिया की हवाई सीमा में किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में नाटो ने 'आपरेशन ईस्टर्न सेंट्री' शुरू किया है, जो उसकी सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाता है। इसी के साथ यूक्रेन को मदद के लिए 'प्रायोरिटी यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से अत्याधुनिक हथियार प्रणाली उपलब्ध कराई जा रही है।

इन घटनाक्रमों का एशियाई क्षेत्र से सीधा संबंध भले न लगे, लेकिन इनके निहितार्थ स्पष्ट हैं। भविष्य में नाटो का विस्तार और रणनीतिक बदलाव एशिया की सुरक्षा व शक्ति-संतुलन को गहराई से प्रभावित करेंगे। भारत के लिए यह अवसर और चुनौती दोनों है। वस्तुतः नाटो की नीतियां अब केवल यूरोप की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह स्वयं को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे एशियाई देशों को उसने 'पार्टनर्स अक्रास द ग्लोब' के रूप में जोड़ा है। इन देशों के साथ बढ़ता सहयोग स्पष्ट करता है कि नाटो का अगला ध्यानक्षेत्र एशिया और विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक है। इसका प्रमुख कारण चीन और रूस के साथ का बढ़ता समीकरण है, जो नाटो की रणनीति के लिए चुनौती बन रहा है।

भारत और नाटो के बीच अब तक का संबंध काफी दूरी भरा रहा है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाया और किसी सैन्य गठबंधन से दूरी बनाए रखी। रूस के साथ उसके पुराने रक्षा सहयोग और स्वतंत्र विदेश नीति की प्राथमिकताओं ने भी इस दूरी को बनाए रखा। हालांकि, बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत और नाटो के बीच संवाद की शुरुआत हुई है। बीते कुछ वर्षों में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी रणनीति और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने एशियाई क्षेत्र को परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। ऊर्जा संकट, अनाज आपूर्ति में असंतुलन और रक्षा उद्योग पर दबाव ने एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। भारत ने इस संकट में संतुलन की नीति अपनाई, एक ओर रूस से तेल आयात जारी रखा, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाया। लेकिन नाटो द्वारा रूस के खिलाफ लगातार बढ़ती कार्रवाई ने एशिया के देशों को दो हिस्सों में बांट दिया है। जापान, दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया जैसे देश नाटो के करीब खड़े हैं, जबकि भारत और वियतनाम जैसे देश अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहते हैं। यह विभाजन आने वाले समय में एशिया की सुरक्षा संरचना को पुनर्गठित कर सकता है।

चीन का प्रश्न यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है। चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है, ताइवान पर दबाव बना रहा है और आर्कटिक तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। साथ ही, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वह आर्थिक और सुरक्षा दोनों प्रकार के नेटवर्क बना रहा है। रूस के साथ उसकी बढ़ती साझेदारी नाटो के लिए भी चिंता का विषय है। भारत के लिए भी चीन सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है, चाहे वह सीमा विवाद हो या हिंद महासागर में उसका विस्तारवादी रुख। इस संदर्भ में नाटो की कुछ हद तक चीन-विरोधी रणनीति भारत के लिए अवसर और खतरे, दोनों पैदा करती है। इसे भी ध्यान में रखना होगा।

भारत की रणनीतिक स्थिति यह है कि वह क्वाड, आइ2यू2 व ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से वैश्विक शक्ति संरचना में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। नाटो के बढ़ते वैश्विक दायरे का असर भारत पर तीन स्तरों पर होगा। पहला, सुरक्षा सहयोग के स्तर पर भारत परोक्ष रूप से तकनीकी और साइबर सुरक्षा सहयोग प्राप्त कर सकता है। दूसरा, कूटनीतिक संतुलन पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि नाटो के नजदीक आने से रूस-भारत संबंधों में तनाव संभव है। तीसरा, रक्षा उद्योग में भारत को नई तकनीक और निवेश के अवसर मिल सकते हैं।

भविष्य में नाटो के भीतर होने वाले बदलाव एशिया की भू-राजनीति को कई तरह से प्रभावित करेंगे। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नाटो की स्थाई उपस्थिति संभव है, खासकर जापान या आस्ट्रेलिया में किसी लाजिस्टिक्स बेस के रूप में। साझा सैन्य अभ्यास बढ़ेंगे और साइबर व अंतरिक्ष सुरक्षा में एशियाई देशों के साथ साझेदारी गहरी होगी। यदि दक्षिण चीन सागर या ताइवान को लेकर संकट बढ़ता है, तो नाटो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। भारत के लिए इन बदलावों में अवसर भी हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, वैश्विक दक्षिण की आवाज को मंच मिलना और हिंद महासागर में संतुलन बनाए रखना ऐसे लाभ हैं जिनसे भारत अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। वहीं, चुनौतियां भी गंभीर हैं, रूस की नाराजगी, चीन के साथ बढ़ता तनाव और रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठना। इसलिए भारत को नाटो के साथ किसी औपचारिकता में जाने के बजाय 'चयनात्मक सहयोग' की नीति अपनानी होगी।

बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नाटो द्वारा लिए जा रहे हालिया निर्णयों का असर भारत पर भी हो सकता है। फाइल

भारत के लिए रणनीतिक संतुलन की नई चुनौती

रवि बिश्नोई

यह समय भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा का है, जहां हर कदम नापा-तौला होना चाहिए। रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक शक्ति संतुलन को पहले ही हिला दिया था। अब नाटो की बदलती भूमिका और एशिया में उसका सक्रिय हस्तक्षेप इस तस्वीर को और जटिल बना रहा है। नाटो अब केवल एक यूरो-अटलांटिक सुरक्षा ढांचा नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं को वैश्विक शक्ति-संतुलन का निर्णायक स्तंभ बनाने में जुटा है। नाटो की गतिविधियों ने साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब "तटस्थता" का स्थान सिकुड़ता जा रहा है। भारत को तय करना होगा कि वह इस नए परिदृश्य में अपनी भूमिका कैसे परिभाषित करता है।

रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित जापद-2025 सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी को पश्चिम ने बहुत गंभीरता से लिया। भारत का यह कदम संकेत देता है कि वह रूस के साथ दशकों पुराने रक्षा सहयोग को पूरी तरह त्यागने के मूड में नहीं है। रूस ने इस अभ्यास के दौरान नई रक्षा रणनीतियों का प्रदर्शन किया, जिसमें भारत की उपस्थिति को पश्चिमी विश्लेषक "रूस की कूटनीतिक जीत" के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभ्यास केवल सैन्य सहयोग की निरंतरता है, न कि पश्चिम विरोधी गठबंधन में शामिल होने का इशारा।

इसी बीच नाटो महासचिव ने भारत समेत कई देशों को चेतावनी दी कि यदि वे रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह बयान भारत के लिए प्रत्यक्ष दबाव है, क्योंकि भारत वर्तमान में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने जवाब में यह कहा कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं किसी भी गठबंधन के राजनीतिक एजेंडे से बड़ी हैं और वह किसी भी "दबाव की राजनीति" को स्वीकार नहीं करेगा।

यूरोप के मोर्चे पर नाटो ने ईस्टर्न सेंट्री शुरू कर दिया है। रूस की सीमा से लगे क्षेत्रों में निरंतर तनाव, मिसाइल हमलों और ड्रोन घुसपैठ ने नाटो को सतर्क कर दिया है। इस कदम का असर परोक्ष रूप से भारत पर पड़ता है, क्योंकि रूस पर दबाव और बढ़ने का मतलब है कि रूस को भारत से और अधिक निकटता की आवश्यकता होगी। एशिया में नाटो की भूमिका अब सबसे अधिक चर्चा में है। हाल ही में फिलीपींस और वियतनाम को भी सुरक्षा वार्ता में शामिल करने की कवायद जारी है। भारत इस मोर्चे पर स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। लेकिन भारत खुले तौर पर नाटो के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से उसके रूस और चीन दोनों के साथ संबंध संकट में पड़ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वह दोनों खेमों में संतुलन बनाए।

लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की परिस्थितियों में यह संभव है? नाटो के बढ़ते दबाव और रूस-चीन के बदलते समीकरण भारत को मजबूर कर रहे हैं कि वह अपने रुख को और स्पष्ट करे। भारत का सहयोग समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों और तकनीकी साझेदारी तक सीमित रहेगा। उसने किसी अन्य सैन्य गठबंधन से परहेज किया। फिर भी, भारत के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। अगर नाटो रूस पर और कठोर होता है और पश्चिमी प्रतिबंधों का दायरा बढ़ता है तो भारत को आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ, यदि भारत रूस से दूरी बनाता है तो उसकी रक्षा आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक साझेदारी पर संकट आ सकता है। **(लेखक हिंद-प्रशांत मामलों के शोधार्थी हैं)**

नाटो का बदलता स्वरूप और उसका विस्तार एशियाई क्षेत्र को प्रभावित करेगा। भारत के सामने चुनौती होगी कि वह इस नई संरचना में अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन में योगदान भी दे। भारत के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता यही होगा कि वह नाटो को साझेदार और संवाद मंच के रूप में देखे, पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे। यही संतुलन भारत को भविष्य की अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थिर और मजबूत बनाएगा।

खरी-खरी

घर-घर की रामलीला

पूरन शर्मा

आजकल घर की रामलीला निपट जाए, यही बड़ी बात है। रामलीलाओं का मौसम है और जीवन में राम के उच्चादर्शों की स्थापना के लिए इनका मंचन हो रहा है। परंतु हमारे घरेलू रंगमंच पर जो लीला चल रही है, उसका अंत क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। भारतीय संस्कृति में लीलाधरों के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लीलाएं इधर चल रही हैं वे नए सोच और अंदाज को जन्म दे रही हैं। बचपन में जो रामलीला किया करते थे, वह मनोरंजन के लिए थी। यह तनिक भी पता ही नहीं था कि यह मनोरंजन एक दिन जीवन का यथार्थ ही बन जाएगा। आज हालात ऐसे हैं कि रावण के किरदार के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। आसानी से मैं उन्हें सुलभ हो जाता हूं।

प्रारंभ में गांव में जो रामलीला होती थी, उनमें हनुमान ही तलाश रहती थी, परंतु कोई भी फिट नहीं हो पाता था। अंत में चेहरे, नाक-नक्श में हनुमानजी से मिलती-जुलती मेरी सूरत को देखकर मुझे ही जीवंत भूमिका करने के लिए जोर डाला जाता था। बहुत दिनों तक यह चेहरा हनुमान के रोल में काम आता रहा, बाद में यही रावण के अनुकूल बन गया तो रामलीलाओं में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं रामलीला का प्रमुख खलनायक रावण बन बैठा। बहुत ही सनसनीखेज दिन थे वे। आज भी सोचता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं।

परंतु होनी को कौन टाल सकता है? शादी हुई और मंदोदरी का शिकंजा मेरे ऊपर कसता चला गया। जो रावण रामलीला में सीता को हर लाया करता था, अब तो पराई स्त्रियों पर नजर डालने में भी शामत देखने लगा। सारी दहाड़ें, चीख-पुकार, रौब-दाब सब हवा हो गया। घर की रामलीला में परास्त होना लोगों के लिए ही हैरतअंगेज नहीं, अपितु स्वयं मेरे लिए भी था। समझ ही नहीं पाता था कि अकस्मात मुझे हुआ क्या है? निरीह गाय की तरह जिस खूंटे चाहो बांध दिया जाता।

इस बीच घर में मेघनाद का आगमन हुआ। वह सचमुच मेघनाद था। मेघ की गर्जन करने लगा तो स्वयं मैं और मेरी मंदोदरी सहम जाते थे। पूत के पग पालने में दिख आए थे। उसने बिना पूजा-अर्चना व तपस्या के ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिए तथा इंद्र तक उससे डरने लगे थे।

पोस्ट

पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतें देखकर यही लगता है कि इनकी तमन्ना एक अच्छा खिलाड़ी बनने से ज्यादा जैश जैसे आतंकी संगठन का रंगरूट बनने की है।
अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

पाकिस्तानी क्रिकेटर का अपने बल्ले को एके-47 की तरह लहराना मात्र एक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक गहरी समस्या का संकेत है। वहां जवटर से लेकर क्रिकेटर तक लगभग हर तबके को जिहादी मानसिकता की घुट्टी पिलाई गई है। कट्टरपंथ और फौजी वर्चस्व ने हिंसा को ही संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। कूटनीति तो सभ्य देशों के साथ की जाती है, लेकिन पाकिस्तान केवल ब्रह्मोस की भाषा समझता है।
जहाक तनवीर@ZahackTanvir

गाजा के लिए पाकिस्तान के जिन पंजाबियों का दिल पसीजता है, वही अपनी सेना द्वारा पश्तूनों के कत्लेआम पर या तो खामोश है या उसके बचाव में लगे हैं। कुछ तो इसका जश्न तक मना रहे हैं। भले ही पश्तूनों को पाकिस्तान में दोयम दर्जे का माना जाता हो, लेकिन वे भी पाकिस्तानी नागरिक ही तो हैं।
सुशांत सरीन@sushantsareen

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या घटी हुई जीएसटी दरें उपभोग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्तरहीन खेल भारत से मुकाबले लायक नहीं रह गया है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

धो डाला अभिषेक ने गिल का गजब प्रहार,
फिर से पाकिस्तान के गले पड़ गई हार।
गले पड़ गई हार हाथ कुछ भी ना आया,
मार तिलक ने चार जीत का 'तिलक' लगाया।
बस बंदूक चलाय करे अपना मुंह काला,
भारत ने इक बार क्रिकेट में फिर धो डाला!
- ओमप्रकाश तिवारी

बंगाल डायरी

ममता के वार पर भाजपा का पलटवार

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस हथियार से भाजपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, भाजपा ने अब उसी हथियार से पलटवार शुरू कर दिया है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी द्वारा भाजपा पर बांग्ला भाषा का अपमान और बंगाल के बाहर प्रवासी बंगालियों के उत्पीड़न के ये दो प्रमुख आरोप बार-बार लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेता सार्वजनिक रूप से कहते आ रहे हैं कि इन बेबुनियाद आरोपों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने तृणमूल के खिलाफ प्रवासी बंगालियों को ही मैदान में उतारकर एक साथ हिसाब चुकता करने की रणनीति पर कार्य तेज कर दिया है।

बंगाल के भाजपा नेताओं ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर वहां रहने वाले प्रवासी हिंदू बांग्लाभाषियों और उनके द्वारा संचालित पूजा समितियों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने हरियाणा और चंडीगढ़ का पांच दिवसीय दौरा किया और वहां रहने वाले प्रवासी बांग्लाभाषियों के साथ बैठकें कीं। वह हरियाणा और चंडीगढ़ में रहने वाले प्रवासी बांग्लाभाषियों से मिले और उनसे बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाने के लिए अपने मताधिकार के उपयोग को लेकर जागरूक रहने की अपील की। यही नहीं, बंगाल भाजपा के वर्तमान एवं एक और पूर्व अध्यक्ष भी दूसरे राज्यों में जाने वाले हैं। वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गृह राज्य गुजरात, जबकि केंद्रीय मंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं।

अन्य राज्यों में बंगालियों के बीच बंगाल के भाजपा नेताओं के जनसंपर्क की यह योजना भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तैयार की है। इस कार्यक्रम के लिए भाजपा ने प्रत्येक राज्य में स्थानीय नेताओं की टीमें बनाई हैं। ये टीमें बंगाल भाजपा के नेताओं को स्थानीय पूजा समितियों तक ले जा रही हैं। राज्य के भाजपा नेता दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई, पुणे, नासिक, सूरत, जयपुर, रांची, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, बेंगलुरु, पणजी, मडगांव जैसे विभिन्न शहरों में जा रहे हैं।

शमिक भट्टाचार्य। फाइल

सुकांत मजूमदार। फाइल

राहुल सिन्हा। फाइल

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा को हरियाणा और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी। अमिताभ राय को अंडमान भेजा गया था। वे अपना काम पूरा कर पहले ही लौट चुके हैं। राहुल ने कहा, 'यह कार्यक्रम बंगाल के बाहर रहने वाले बंगालियों को बंगाल की स्थिति से अवगत कराने का है। कहीं भी बंगालियों का कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। लोगों को तृणमूल और ममता बनर्जी द्वारा गढ़ी गई कहानियों पर विश्वास नहीं है।' वह आगे कहते हैं, 'हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं या जाएंगे, उनमें से ज्यादातर उस राज्य के मतदाता हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार या परिचित इसी राज्य में रहते हैं। ये प्रवासी उन्हें बताएंगे कि दूसरे राज्यों ने कितनी तरक्की की है और तृणमूल को इस राज्य से क्यों हटाना जरूरी है।' लाकेट चटर्जी देहरादून और हरिद्वार की पूजा समितियों से मिलकर लौटी हैं। केया घोष दिल्ली में पूजा समितियों से मिलकर आई हैं।

बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष रथींद्रनाथ बसु का कहना है कि एक बार फिर वहां जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस पूजा केंद्रित जनसंपर्क को लेकर भाजपा नेता केया घोष ने कहा, 'दिल्ली में मैं जिस किसी से भी मिली, उसने मुझे यह समझाने की कोशिश की कि मैं बंगाल के बाहर बंगाल के एक हिस्से में रह रहा हूं। मैं तीन दिन रुकी। वहां शमिक और सुकांत के दौरे को लेकर भी काफी चर्चा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह प्रधानमंत्री का राज्य और निर्वाचन क्षेत्र है। दो शहर- सूरत और वाराणसी इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सूरत में प्रवासी बंगालियों में से कई बंगाल के मतदाता भी हैं, हालांकि वाराणसी के ज्यादातर बंगाली कई पीढ़ियों से उसी शहर के निवासी हैं। वे न केवल वहां के मतदाता हैं, बल्कि वाराणसी की राजनीति पर उनका प्रभाव भी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा, 'उनका दौरा दुर्गापूजा के बाद होगा। यह दौरा केंद्र सरकार का 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम का हिस्सा है। उत्सव के दौरान लोगों का जमावड़ा अधिक होता है, इसीलिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।'

वहीं सुकांत मजूमदार आज वाराणसी पहुंचेंगे और बांग्लाभाषियों की दुर्गापूजा आयोजन समितियों के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। वैसे तो राज्य भाजपा नेतृत्व इसे न तो चुनाव और न ही ममता के आरोपों के जवाब से जोड़ रहा है, पर राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा का प्रवासी बंगाली हिंदुओं के माध्यम से ममता पर पलटवार और बंगाल के लोगों तक सच पहुंचाने का प्रयास मान रहे हैं।

मंथन

विकास का सर्कुलर माडल

विश्व में आपदाओं का एक बड़ा कारण विकास का उपभोक्तावादी आर्थिक माडल भी है, जिसमें वस्तुओं के अत्यधिक उपयोग एवं उपभोग को सामाजिक समृद्धि का द्योतक समझा जाने लगा है

प्रो. एच. सी. पुरोहित
डीन, स्कूल आफ मैनेजमेंट, दून विवि, देहरादून

विश्व के अधिकांश देश आज किसी न किसी आपदा से ग्रस्त हैं। इनमें प्राकृतिक और मानवजनित दोनों तरह की आपदाएं शामिल हैं। इन आपदाओं का प्रभाव उन देशों पर भी है जो कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जैसे कैरेबियन, डोमिनिका, अफ्रीका का कोमोरोस आदि देश। चूंकि पर्यावरण संकट या जलवायु परिवर्तन किसी देश की सीमा तक सीमित न होकर यह समूचे भू-मंडल को प्रभावित करता है, संभवतः इसलिए ऐसा हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों के अनुसार, आपदा से विस्थापित होने वालों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2023 में आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन लगभग 77 लाख था। वर्ष 2024 में यह आंकड़ा लगभग साढ़े चार करोड़ था। अनुमान है कि यह संख्या वर्ष 2050 तक 1.2 अरब से अधिक हो जाएगी। आपदाओं से होने वाला पलायन युद्ध के कारण होने वाले पलायन से दस गुना अधिक है।

वैश्विक पीड़ा का बड़ा कारण : आपदाग्रस्त विश्व समुदाय की प्रमुख पीड़ा का कारण मानव जनित अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए अपनाए जाने वाले उपभोक्तावाद और बाजारवादी आर्थिक माडल के कारण वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग और उपभोग सामाजिक समृद्धि का भी द्योतक समझा जाने लगा है। इस प्रवृत्ति से समाज में असमानता बढ़ रही है। जहां एक ओर विश्व में करोड़ों लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं, वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर लगभग 73.3 करोड़ लोग भूख से प्रभावित थे यानी वे पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं ले पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक अरब से अधिक टन भोजन बर्बाद होता है।

यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी रेखीय माडल पर आधारित है, जिसमें 'टेक-मेक-डिस्पोज' की नीति प्रचलित है। इस प्रणाली में उत्पादों का पुनः उपयोग नहीं किया जाता और उसे कचरा समझ कर फेंक दिया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में अपशिष्ट और प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इससे प्राकृतिक साधनों का तीव्र क्षरण होने के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हो रहा है। इस मानव जनित आपदा से निपटने के लिए हर देश द्वारा हर वर्ष करोड़ों रुपये व्यय किए जाते हैं, परंतु आपदाओं से जो मानसिक आघात पहुंचता है, एवं जान-माल की क्षति से जो दर्द पहुंचता है, उसकी प्रतिपूर्ति शायद ही कभी हो पाए।

संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग : मानव जनित आपदाओं पर नियंत्रण हेतु मानव समाज को संवेदनशीलता के साथ सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी इस समस्या का दीर्घकालीन समाधान संभव होगा। इसके लिए आर्थिक विकास का रेखीय माडल के बजाय चक्रीय (सर्कुलर) माडल अपनाना होगा। क्योंकि चक्रीय अर्थव्यवस्था का माडल उत्पादन और उपभोग हेतु उत्पादों और सामग्रियों को यथासंभव लंबे समय तक साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण शामिल है, ताकि उन्हें अपशिष्ट बनने से रोका जा सके और कचरे को कम किया जा सके। चूंकि यह 'रिसाइकिल, रियूज, रिड्यूस, रिपेयर' के सिद्धांत पर आधारित है, लिहाजा इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा। इसके लिए ग्रास इकोसिस्टम प्रोडक्ट (जीईपी) की गणना की जानी चाहिए। ऐसा करने से प्रकृति से मिलने वाली निशुल्क सेवाएं जैसे आक्सीजन, जैव विविधता, जल संरक्षण आदि लगभग डेढ़ दर्जन सेवाओं का मूल्यांकन प्रकृति के प्रति समाज को संवेदनशील बनाएगा और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करेगा। सतत विकास के लिए उपभोग की जगह प्रकृति संरक्षण, रेखीय के बजाय चक्रीय माडल अपनाने तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की व्यापकता और सार्वभौमिकता का मापन जरूरी है। भारत में इकोसिस्टम सर्विसेज की गणना हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. एस. पी. सिंह ने हिमालयी वन पारिस्थितिकी प्रणालियों पर वर्ष 2002 के शोध पत्र द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को जैविक और अजैविक घटकों के बीच परस्पर क्रिया से प्राप्त लाभों के रूप में प्रकाशित किया, जिसमें कार्बन पृथक्करण, मृदा उर्वरता में सुधार, मृदा और वायु शोधन, और जलवायु नियंत्रण शामिल हैं।

प्रतीकात्मक

इकोसिस्टम सर्विसेज की गणना की शुरुआत अमेरिका के विज्ञानी राबर्ट कोस्टांजा ने की, जिन्होंने 1997 में अपने शोध पत्र के माध्यम से दुनिया को इस विषय की ओर आकर्षित किया, और पारिस्थितिकी तंत्र की 17 इकोसिस्टम सर्विसेज की पहचान की। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव ने इसे 'मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट' के रूप में अपनाया। इकोसिस्टम सर्विसेज की गणना कई देशों में छोटे स्तर पर की जाती है, परंतु समग्र रूप से वैश्विक स्तर पर यह प्रचलन में कम ही है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गणना और उस आधार पर अर्थव्यवस्था का मापन करने से पर्यावरण संकट तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

चिंतन

देश की प्रतिभाओं को आकर्षित करने का मौका

दुनिया की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। एक के बाद एक ऐसे फैसले आमने आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं। सबसे ज्यादा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौंका रहे हैं। उन्होंने एकाएक एच-1बी वीजा के नियमों में संशोधन करके भारतीय पेशेवरों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। अब अगला फैसला चीन की तरफ से आया है। अपने विकास और अपनी तकनीक को हमेशा गोपनीय रखने वाले चीन ने दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करने के लिए एक नई के वीजा कैटेगरी की शुरुआत करने का ऐलान किया है। वैसे तो चीन की नई वीजा कैटेगरी को लेकर फैसला अगस्त में ही कर लिया गया था। लेकिन अब एक अक्टूबर, 2025 से ये लागू हो जाएगी। अमेरिका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की फील्ड से जुड़े लोगों को एच-1बी वीजा के जरिए देश में लाता रहा है, लेकिन अब यही काम चीन करने वाला है। कई देशों में वर्किंग प्रोफेशनल्स की एंट्री कड़ी की जा रही है। ऐसे में चीन ने इसका फायदा उठाते हुए नए वीजा को लॉन्च किया है, ताकि वह उन्हें देश में लेकर आ सके। दरअसल, अमेरिका ने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर में जिस तरह का दबदबा बनाया है, उसके पीछे एच-1बी वीजा का बड़ा हाथ रहा है। बिना एच-1बी वीजा वर्कर अमेरिका की टेक इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। चीन को ये बात अच्छी तरह से मालूम है, तभी वह चाहता है कि जिन वर्किंग प्रोफेशनल्स को अमेरिका जाने में दिक्कत हो रही है, वो सीधे चीन आ जाएं और उसने कई तरह की सुविधाएं देने का भी वादा किया है। ऐसे में जल्द ही सारे टैलेंटेड लोग चीन का रुख भी कर सकते हैं। आवेदकों को ये वीजा तभी मिलेगा, जब वे चीनी अधिकारियों द्वारा तय की गई क्वालिफिकेशन और शर्तों को पूरा करेंगे। उन्हें इस दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे। हालांकि, अभी वीजा की शर्तों को जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही चीनी दूतावासों और महावाणिज्य दूतावासों की तरफ से इसकी जानकारी पब्लिश की जाएगी। इस फैसले से तय है कि चीन दुनियाभर की प्रतिभा अपने देश में लाने की तैयारी में है। अमेरिका के ही सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच जारी किए गए सभी एच-1बी वीजा में से 70 प्रतिशत से ज्यादा भारतीयों को मिले हैं। ट्रंप सरकार स्वदेशियों को रोजगार के अवसर की आड़ लेकर अपने यहां स्किल्ड अप्रवासियों के रास्ते धीरे-धीरे बंद कर रही है। एक तथ्य यह भी है कि अमेरिका की कई नामी कंपनियां भारतीय पेशेवरों के भरोसे ही रहती आई हैं। अमेरिका में भारी वीजा फीस देनी पड़ी तो ये कंपनियां भी अपने कार्यालय भारत व दूसरे देश में खोलने का विकल्प रख सकती हैं। अब चीन चाहता है कि ये कंपनियां उनके देश में आ जाएं। हमें भी चीन की तरह तुरंत कदम की उठाने की जरूरत है ताकि हमारे युवा अपने ही देश में रहकर विकास को रफ्तार दें। इसके लिए अभी कई तरह के प्रयास करने होंगे। क्योंकि वेतन व जीवनशैली से जुड़ी सुविधाओं का इन प्रयासों में खासा योगदान रहने वाला है। अभी हमारे शहरों में ऐसे पेशेवरों के लिए बुनियादी सुविधाओं की दिशा में काफी कुछ करना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे आइटी शहरों में पेशेवरों और स्टार्टअप्स को आकर्षित करने का यह बेहतर मौका है। समुचित सुविधाएं देने के साथ अपने ही देश में पेशेवरों को रोक कर 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में कदम तेज किए जा सकते हैं। बस जरूरत है कि कदम आगे बढ़ाने की।

पहल
अवधेश कुमार

संबोधन का दूरगामी महत्व

> प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उनकी पार्टी के शीर्ष लोग भी बोलते हैं की उनका पूर्व अनुमान लगाना लगभग असंभव होता है। इस कारण शायद देश के बड़े समूह की उम्मीदें ज्यादा रही होंगी। इस समय जिस तरह की चुनौतियां भारत के सामने उत्पन्न हुई हैं, सोशल मीडिया में इतनी बातें आती है कि लोग सभी में शीर्ष नेतृत्व से प्रतिक्रिया की मांग करने लगते हैं। उसमें यदि कुछ लोगों को लगता है कि इतने के लिए संबोधन की आवश्यकता नहीं थी तो यह उनकी सोच हो सकती है। सच कहा जाए तो किसी संबोधन का छोटा होना उसके आवश्यक, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण न होने का पर्याय नहीं हो सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन लगभग 19 मिनट का था। विरोधियों की आम प्रतिक्रिया यही है कि केवल जीएसटी या वस्तु और सेवा कर सुधार की ही बात रखनी थी तो उसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई विश्लेषकों और पत्रकारों ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसी तरह का पोस्ट लिखा है। मोदी की छवि अच्छे प्रभावी होने के साथ लोगों की समझ में आ जाए इस तरह से बात रखने वाले वक्ता की है। जैसे ही यह सूचना आई कि प्रधानमंत्री शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे अनेक तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उनकी पार्टी के शीर्ष लोग भी बोलते हैं की उनका पूर्व अनुमान लगाना लगभग असंभव होता है। इस कारण शायद देश के बड़े समूह की उम्मीदें ज्यादा रही होंगी। इस समय जिस तरह की चुनौतियां भारत के सामने उत्पन्न हुई हैं, सोशल मीडिया में इतनी बातें आती है कि लोग सभी में शीर्ष नेतृत्व से प्रतिक्रिया की मांग करने लगते हैं। उसमें यदि कुछ लोगों को लगता है कि इतने के लिए संबोधन की आवश्यकता नहीं थी तो यह उनकी सोच हो सकती है। सच कहा जाए तो किसी संबोधन का छोटा होना उसके आवश्यक, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण न होने का पर्याय नहीं हो सकता।

2017 में जीएसटी की शुरुआत के समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था और उसे आर्थिक आजादी की शुरुआत बताया था। अप्रत्यक्ष करों में इतनी बड़ी कटौती केवल दो दरों 5 प्रतिशत और 18% तक सीमित कर देने जैसे ऐतिहासिक कदम पर वे देश को संबोधित नहीं करें ऐसा संभव नहीं था। उसमें भी इस वर्ष के बजट में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया। ध्यान रखिए, 15 अगस्त को लाल किले के संबोधन से ही उन्होंने सेकंड जेनरेशन रिफॉर्म यानी दूसरी पीढ़ी के सुधारों की बात की थी और इसे सतत प्रक्रिया बताया था। इस नाते जीएसटी दरों में परिवर्तन का क्रांतिकारी महत्व है। शारदीय नवरात्र और ग्रेगोरियन कैलेंडर से 22 सितंबर से इसकी शुरुआत करने का महत्व भी समझ जाना चाहिए। आखिर नौ दिनों का यह त्योहार शरीर और चित्त की शुद्धि ही नहीं अपनी साधना से बहु स्वरूपा मां दुर्गा को प्रसन्न कर सिद्धि प्राप्त करने की भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं दासत्वकाल के अवशेषों और मानसिकता से मुक्ति का बार-बार आह्वान किया है। शुभ मुहूर्त में देवी देवताओं की आराधना के साथ कार्य शुरू करने की हमारी परंपरा है। नवरात्र के आरंभ जैसी अवसरों से अपने व्यापक आर्थिक सुधार के इतने महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत करते हैं तो राष्ट्र के नाम संबोधन से इसका महत्व स्पष्ट होता है। प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भव, बचत उत्सव से लेकर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बातचीत की। वर्तमान विश्व परिदृश्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संचालन के लिए कोई नियम या तंत्र नहीं है। सभी देशों को अपनी आंतरिक व बाह्य शक्ति के आधार पर ही अस्तित्व बनाए रखने और कार्य करने का यथार्थ सामने है। भारत के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% सीमा शुल्क फिर रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% शुल्क लागू कर दिया। अमेरिका विपक्षीय व्यापार में हमारा सबसे ज्यादा

42 से 43 अरब डॉलर का लाभ देने वाला देश है। यहां हमारे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात प्रभावित हुए तो इसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ना है। आप इसका आकलन अपने अनुसार कर सकते हैं। शायद सामान्य समय में भारत रूस से तेल आयात में थोड़ी बहुत कमी कर सकदी और अन्य जगहों से बढ़ा सकता था। किंतु अभी ऐसा करने का अर्थ देश का दबाव में झुक जाना होगा और इसका आर्थिक प्रभाव भी होगा। विश्व को दिशा देने का लक्ष्य रखने वाला देश कदापि ऐसा नहीं कर सकता। तो यह एक अवसर है हमें भविष्य की दृष्टि से सचेत होकर कदम उठाने का ताकि आने वाले समय में इससे बड़े आघात भी राष्ट्र के रूप में भारत को प्रभावित नहीं कर सकें।

रक्षा, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समीकरणों की दृष्टि से भी संपूर्ण विश्व उथल-पुथल के दौर में है। थोड़ी गहराई से देखें तो यह विचारधाराविहीनता का भी युग है जहां संपन्न व प्रभावी व्यक्तित्व, संस्थाएं, संगठन, समूह, समुदाय किसी देश में उथल-पुथल का खतरा पैदा कर सकते हैं। इन सबसे निपटने का कोई एक रास्ता हो सकता है तो यही कि भारत हर दृष्टि से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं और आत्मनिर्भरता का रास्ता राष्ट्र के प्रति स्वभाव के अभियान और स्वदेशी से जाता है। प्रधानमंत्री स्वयं लंबे समय से लोकल फौल वोकल की बात तो करते ही रहे हैं।

इन सारे परिप्रेक्ष्यों को आधार बनाएं तो निष्कर्ष आएगा कि प्रधानमंत्री ने छोटे संबोधन में ही राष्ट्र के लिए एक क्रांति का आह्वान किया है। उन्होंने उद्यमियों, एक-एक व्यक्ति, सभी राज्यों से अपील की है कि मिलजुल कर इस तरह से कम करें, ऐसे नियम बनाएं ताकि स्वदेशी सोच व संसाधनों की बदौलत आत्मनिर्भर बन सकें। यही एकमात्र रास्ता है जिसके बाद कोई देश हमको आर्थिक, सैन्य, तकनीक, वैज्ञानिक किसी दृष्टि से दबावों में लाने का दुस्साहस नहीं करेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में सामान्य विदेश नीति ,,कूटनीति ही नहीं विपक्ष के आरोपों का उत्तर या विपक्ष पर राजनीतिक हमले नहीं किए जाते। कांग्रेस के जयराम रमेश या अन्य नेताओं के पूर्व कटाक्षों से आप प्रभावित केवल भारत के भविष्य का विचार करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के नेता के रूप में सभी से इन परिस्थितियों में भारत राष्ट्र के नाते सोचने और उस दृष्टि से संगठित होकर काम करने का आह्वान किया है।

25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया जो नवमध्यम वर्ग है। इसकी अभिक्षाएं हैं जो बहुत कुछ करने और पाने को तत्पर है। दूसरे , भारत में सुधारों के कारण नियम-कानूनों को इतना आसान कर दिया गया है कि एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य और अनेक मायनों में देशव्यापी उद्यम, कारोबार और आवागमन सहित आपूर्ति श्रृंखला में पहले की तरह समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री ने उदाहरण भी दिया कि बेंगलुरु से हैदराबाद सामान पहुंचाने में इतने कर देने पड़ते थे कि उत्पादक पहले उसे यूरोप भेज कर वहां से हैदराबाद मांगना आसान समझते थे। यह उदाहरण देश और विदेश के पूंजी निवेशकों के लिए भी था कि भारत बदल चुका है। पहले बड़े आय को कर मुक्त करने अप्रत्यक्ष कर भी केवल पांच प्रतिशत और 18% तक सीमित करने का अर्थ घरों में बचत होगा और भारत जैसे व्यापक मध्यवर्ग परिवार के लोग अतिरिक्त पैसों से खरीदारी करेंगे। भारत की दृष्टि से देखें तो नवरात्र के समय से त्योहार का दौर शुरू होता है जिसमें आम परिवार खरीदारी करते हैं। जीएसटी के बदलाव का समय ऐसा चुना गया है कि बाजारों में बिक्री बढ़नी ही है। वैश्विक परिस्थितियों के और बिगड़ने के बावजूद इसका नकारात्मक असर नहीं हो सकता है। इन दृष्टियों से प्रधानमंत्री के संबोधन के तात्कालिक एवं दूरगामी महत्व को समझा जा सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मौसम
पंकज चतुर्वेदी

मानसून को जलवायु परिवर्तन के परिपेक्ष्य में समझना होगा

इस बार उत्तर भारत में मानसून ने लोगों को डरा दिया है। बांध लबालब हैं, नदियों का पानी खेतों में प्रवेश कर गया है। भारत के मौसम विभाग के 2012 से उपलब्ध के आंकड़ों के अनुसार 22 अगस्त से चार सितंबर तक देश के उत्तरी हिस्से में सामान्य से तीन गुना अधिक बारिश हो चुकी है। जो कि पिछले 14 सालों में सबसे अधिक है। पंजाब में आई इस दशक की सबसे भीषण बाढ़ के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है। जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी मार्ग पर बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ है। बारिश के पानी के कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये प्रकृति की नियति है लेकिन यह बड़ी चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब देश के बड़े हिस्से में चरम रूप में सामने आ रहा है। भारत में मानसून पर अब अलनीनो से अधिक असर हिन्द महासागर में हो रहे मौसमी बदलाव का असर है। हिंद महासागर में तेजी से तापमान बढ़ने के चलते अब मानसून में अधिक बदलाव आ रहा है, जिससे कभी-कभी सूखा तो कभी अति वर्षा देखने को मिल रही है। इसका कारण हिंद महासागर का द्विध्रुव जिसे आईओडी कहते हैं। आईओडी अर्थात समुद्री सतह के तापमान का ऐसा अनियमित दोलन है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर की सतह का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में क्रमिक रूप से कम या अधिक होता रहता है। जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच गर्म पानी और वायुमंडलीय दबाव में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है। आमतौर पर आईओडी अप्रैल से मई के बीच विकसित होता है और अक्टूबर में चरम पर होता है। इसके विकास और क्षरण से मानसून के समय और ताकत पर असर पड़ता है। जब पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, इसे सकारात्मक आईओडी कहते हैं। इससे भारतीय उपमहाद्वीप व पश्चिमी हिंद महासागर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जब पूर्वी हिंद महासागर का तापमान पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे हालात को नकारात्मक आईओडी कहते हैं और इससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ वर्षा की तीव्रता में कमी आती है।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर बढ़ती मानवजनित गतिविधियों के कारणए अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। आइआइटीएम पुणे के विज्ञानी राक्सी मैथ्यू कौल के नेतृत्व में हुए अध्ययन में गर्म होते हिंद महासागर से मानसून की बारिश में बदलाव की बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर में समुद्री गर्मी बढ़ रही है और इसका असर भारतीय मानसून पर भी पड़ रहा है। जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च ओशन्स में श्जेनेसिस एंड ट्रेंड्स इन मरीन हीट वेव्स ओवर द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन एंड देयर रिएक्शन विथ समर मानसून नाम से प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर के गर्म होने का सीधा प्रभाव मानसून पर होने का निष्कर्ष निकाला है। जब पश्चिमी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री लहरों का तापमान बढ़ता है तो मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में शुष्क मौसम हो जाता है। इसी के चलते उत्तरी बंगाल की खाड़ी में गर्म हवाएं उठती है इसके चलते दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बरसात में बढ़ोतरी हो रही है है।

बढ़ती मानवजनित गतिविधियों के कारण महासागरों को संभवतः पहले से कहीं अधिक बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लोक जीवन अर्थ व्यवस्थाए पर्व त्योहार का मूल आधार बरसात या मानसून का मिजाज ही है। कमजोर मानसून पूरे देश को सूना कर देता है। इसके बावजूद जब प्रकृति अपना आशीष इन बूंदों के रूप में देती है तो समाज व सरकार इसे बड़े खलनायक के रूप में पेश करने लगते हैं। विडंबना यह है कि हम अपनी जरूरतों में इस तरह का बदलाव लाने को राजी नहीं है। असल में हम अपने मानसून के मिजाज, बदलते मौसम में बदलती बरसात मौसम विज्ञान नहीं है इससे इंजीनियरिंग, ड्रैनेज एसेनिटेशन, कृषि सहित बहुत कुछ जुड़ा है। मानसून प्रबंधन का गहन अध्ययन हमारे समाज और स्कूलों से लेकर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में हो वहीं जफसलों, सड़कों व शहरों में बरसाती पानी के निकासी के माकूल प्रबंधों व संरक्षण जैसे अध्याय हों। खासकर महासागर में हो रहे बदलाव के चलते अचानक चरम बरसात के कारण उपजे संकटों के प्रबंधन पर भी हमें नइ सिरे से रणनीति बनानी होगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

ईश्वर की प्राप्ति

संकलित
दर्शन

जड़ जगत की रचना के लिए ईश्वर की जो शक्ति काम करती है, उसे प्रकृति कहते हैं और चैतन्य जगत की रचना करने वाली शक्ति को जीव कहते हैं। जिस प्रकार दोनों हाथ एक ही शरीर के दो भाग हैं, उसी प्रकार जीव और प्रकृति दोनों ही ईश्वरतत्व के दो अंश हैं। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, असल में वह अखिल आद्यशक्ति का सतोगुणी अंश है। मानवीय उन्नति तो सत्य गुणों को प्राप्त करने से ही हो सकती है। इसलिए उन उच्च गुणों की एक मानसिक प्रतिमा बनाकर उपासना करने का विधान किया गया है। ईश्वर का सत्य गुण अदृश्य रूप से हमारे निकट ही वर्तमान है। उसे अधिक मात्र में खींचकर अपने अंदर भर लेने के लिए प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और ध्यान अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन्हीं चारों के समन्वय को 'उपासना' कहा जाता है। उपासना जितनी ही प्रबल होगी, आकर्षण भी वैसा ही सशक्त होगा और उसी के अनुसार उपास्य देवतत्व की प्राप्ति होगी। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, त्याग, समता और न्याय आदि सद्गुणों का निष्ठापूर्वक जितना अधिक चिंतन किया जाता है, उतनी अधिक उनकी प्राप्ति होती है। उन्नति का क्रम तम से सत की ओर चलना है। जिसने जितना ही सत्गुण अपने में धारण कर लिया, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही उन्नतिशील कहा जाएगा। यदि एक भक्त सत्तत्व की उपासना करता है तो कोई कारण नहीं कि उसे वह प्राप्त न हो। ईश्वर की उपासना का तात्पर्य उसके दिव्य सत्तत्व की आराधना है।

अच्छी बातें जीवन में उतारने पर लाभ मिलेगा

संकलित
प्रेरणा

द्वापर युग में द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने कौरव और पांडव राजकुमारों का गुरु बना दिया था। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को एक पाठ दिया और कहा कि कल इस पाठ को आत्मसात करके आना है। आत्मसात शब्द का अर्थ है जीवन में, अपने आचरण में उतारना। अगले दिन सभी राजकुमार गुरु के आश्रम में पहुंच गए। पढ़ाई शुरू हुई तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन-कौन कल का पाठ याद करके आया है? युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों ने कह दिया कि हमने ये पाठ याद कर लिया है। गुरु ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया है? युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अभी तक ये पाठ आत्मसात नहीं किया है। ये बात सुनकर द्रोणाचार्य हैरान थे। कुछ देर सोचकर गुरु ने कहा कि ठीक है कल याद करके आना। इसके बाद दस दिन बीत गए, लेकिन युधिष्ठिर को वो पाठ अब तक याद नहीं हुआ था। जबकि अन्य राजकुमार युधिष्ठिर से 10 पाठ आगे पहुंच गए थे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर बात क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, जैसे मेरे भाइयों ने ये पाठ याद किया है, वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आपने कहा था कि इस पाठ को आत्मसात करना है। आपने सत्य को जीवन में उतारने का पाठ दिया था और मैं सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहा हूं। जब तक मैं इसे आत्मसात नहीं कर लूंगा, जब तक मैं सत्य को जीवन में नहीं उतार लूंगा, तब तक मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।

अंतर्मन

आज की पाती

कंप्यूटर शिक्षा वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य हो

आधुनिक युग मे कंप्यूटर जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हर काम कंप्यूटर से किया जाता है और आसान हो गया है। दूरसंचार हो या बिजनेस शिक्षा हो या खेलकूद विज्ञान, बैंकिंग हो या मनोरंजन। हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। नई-नई खोजे कंप्यूटर के माध्यम से हो रही हैं। व्यापार कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलीजैंस और रोबोटिक्स ने चिकित्सा के क्षेत्र मे नए आयाम कायम किए हैं। आज हमारे वैज्ञानिक चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। यह भी कंप्यूटर के माध्यम से संभव हो पाया है। सूचनाओं का आदान-प्रदान कंप्यूटरो के माध्यम से हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी ले सकते हैं। सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी क्षेत्रो मे भी कंप्यूटर महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे मे कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए।

-रवि चतुर्वेदी, बलारी

करंट अफेयर

परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग छोड़े अमेरिका : किम

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि उनके जेहन मे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूर्व मे की गई मुलाकातो की अच्छी यादे अब भी ताजा हैं। किम ने साथ ही, लंबे समय से रुकी हुई राजनयिक स्तर की वार्ता बहाल करने के लिए पूर्व शर्त के रूप मे उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार बनाना बंद करने संबंधी मांग छोड़ने की अपील की। रविवार को उत्तर कोरिया की संसद को संबोधित करते हुए किम ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिद्वंद्वी देश दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत शुरू करने का उनका कोई इरादा नहीं है। दक्षिण कोरिया अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप के साथ किम की शिखर बैठको मे मध्यस्थता करने मे मदद की थी। किम की यह टिप्पणी ऐसे समय मे आई है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र मे भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क रवाना होने वाले हैं। उम्मीद है कि वह कोरियाई प्रायद्वीप मे परमाणु तनाव पर और वार्ता की मेज पर उत्तर कोरिया के लौटने के संबंध मे बात कर सकते हैं। ट्रंप के अगले महीने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन मे भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया जाने की भी उम्मीद है।

ऑफ बीट

रोज सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी की कमी

हालिया अध्ययन मे दावा किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एसपीएफ 50+ सनस्क्रीन का उपयोग करता है, विशेष रूप से उन दिनो जब अल्ट्रावायलेट (यूवी) इंडेक्स तीन या उससे अधिक होता है, तो उसमे विटामिन डी की कमी का खतरा बढ़ सकता है। सनस्क्रीन के फायदे जगजाहिर हैं, इसलिए हमारे निष्कर्षों का मतलब यह नहीं है कि हमें एसपीएफ 50+ का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि जो लोग रोजाना एसपीएफ 50+ का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंट लेना शुरू करना पड़ सकता है। यह अध्ययन हाल ही मे 'ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी' मे प्रकाशित हुआ है। इसमे कहा गया है कि हालांकि सनस्क्रीन के उपयोग से त्वचा कैंसर और सनस्पॉट्स जैसी समस्याओं से बचाव होता है, लेकिन नियमित उपयोग से शरीर मे विटामिन डी का स्तर अपेक्षाकृत कम हो सकता है। अध्ययन मे 639 वयस्कों को शामिल किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी राज्यों मे रहते हैं। इन्हें दो समूहों मे बांटा गया। एक समूह को रोजाना एसपीएफ 50+ सनस्क्रीन लगाने को कहा गया, जबकि दूसरा समूह अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार सूर्य सुरक्षा उपाय करता रहा।

ट्रेंड

असाधारण स्नेह

आज सुबह ईटानगर में मेरा स्वागत सचमुच यादगार रहा। वंदे मातरम के नारों और नारी शक्ति व युवा शक्ति की जीवंत उपस्थिति से माहौल उत्साहपूर्ण था। अरुणाचल प्रदेश के लोगों का उत्साह और स्नेह असाधारण था।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

बचत उत्सव

नवरात्र में जीएसटी बचत उत्सव के तहत नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक स्टेशनरी दुकानदार से बातचीत की। दुकानदार ने बताया कि कई स्टेशनरी वस्तुओं पर नेक्स्ट-जेन जीएसटी दरों में कटौती से कीमतें कम हुई हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों को लाभ हुआ है।

- निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री

ऐसा प्रेम नहीं देखा

मैंने अपने जीवन में किसी कलाकार के लिए वह प्रेम नहीं देखा जैसा ज़ुबीन को लेकर असम और पूर्वोत्तर में है। दो दिन से प्रदेश नम में है। मुख्यमंत्री से लेकर गोद में शिशु लेकर रास्तों पर खड़ी माँएँ उसके गाने गा-गाकर रो रही हैं।

-कुमार विश्वास, हिन्दी कवि

जीएसटी में सुधार

प्रधानमंत्री ने जीएसटी काउंसिल जो एक संवैधानिक निकाय है, द्वारा किए गए संशोधनों का श्रेय खुद को देने की कोशिश की। कांग्रेस लंबे समय से यह तर्क देती आई है कि जीएसटी में सुधार जरूरी है।

- जयराम रमेश, कांग्रेस नेता

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com